मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | जबलपुर, बुधवार 04 नवंबर 2026 | वर्ष-08, अंक-34, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में जंगलों से लेकर सिंचाई तक बजट मंजूर

विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे 23,300 करोड़ रुपये से ज्यादा

एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा, सिंचाई परियोजनाओं, शहरों की सुविधाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए 23,300 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। सबसे बड़ी राशि वन विभाग की योजनाओं के लिए रखी गई है। वहीं, सिंचाई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए 4,103 करोड़ रुपये और शहरों में सड़क, पानी, सफाई जैसी सुविधाएं बढ़ाने के लिए 700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

कैबिनेट ने वन विभाग की नौ योजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने के लिए 17,240 करोड़ 55 लाख रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक खर्च की जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा 10,664 करोड़ 79 लाख रुपये वन विभाग के कामकाज, मैदानी कार्यालयों और वन वृत्तों के संचालन पर खर्च होंगे। इसके अलावा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 1,994 करोड़ 30 लाख, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए 1,623 करोड़ 79 लाख और लकड़ी उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1,107 करोड़ 6 लाख रुपये रखे गए हैं। जू और रेस्क्यू सेंटर के लिए 604 करोड़ 23 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत उज्जैन और जबलपुर में नए केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन योजनाओं में जंगलों की सुरक्षा, बाघों की निगरानी, वनकर्मियों को प्रशिक्षण और वन्यजीवों के बचाव जैसे काम शामिल हैं। प्रदेश के नौ टाइगर रिजर्व और 10 राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण पर भी राशि खर्च होगी।



कैबिनेट ने पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और उज्जैन की चार सिंचाई परियोजनाओं को आगे जारी रखने के लिए 4,103 करोड़ 73 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इन परियोजनाओं से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने के साथ कुछ क्षेत्रों की पेयजल जरूरत भी पूरी होगी। - पन्ना की मझगांव परियोजनाः इसके लिए 69 करोड़ 36 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। परियोजना से 13,060 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा विकसित होगी।

विदिशा की टेम मध्यम परियोजना: इसके लिए 277 करोड़ 52 लाख रुपये मिलेंगे। इससे 12,814 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा। आसपास के इलाकों की पेयजल जरूरत भी पूरी होगी।

सीतापुर-हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना: मऊगंज, सीधी और सिंगरौली के लिए बन रही इस परियोजना पर 3,620 करोड़ 82 लाख रुपये खर्च होंगे। सोन नदी पर बैराज बनाकर 1.20 लाख हेक्टेयर जमीन तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने की योजना है।

सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना: उज्जैन में शिप्रा नदी में सालभर पानी बनाए रखने के लिए 136 करोड़ 3 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। बारिश के दौरान शिप्रा का पानी सिलारखेड़ी बांध में जमा किया जाएगा और जरूरत के मुताबिक वापस नदी में छोड़ा जाएगा।

शहरों में सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट के लिए 700 करोड़

शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को दो साल और जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके लिए 700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। योजना की अवधि 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक रहेगी। इस राशि से शहरों में पेयजल व्यवस्था, सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था और सामुदायिक भवनों से जुड़े काम कराए जाएंगे। श्मशान घाट, रैन बसेरे और खेल मैदानों जैसी सुविधाओं पर भी खर्च किया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन से जुड़े काम भी इस योजना में शामिल हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा

प्रदेश में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 610 करोड़ 51 लाख रुपये खर्च करेगी। इसके लिए उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को पूंजीगत सुविधाएं विकसित करने पर सब्सिडी दी जाती है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी।

लोकायुक्त संगठन के संचालन पर खर्च होंगे 573 करोड़

कैबिनेट ने लोकायुक्त संगठन के कामकाज के लिए अगले पांच साल में 573 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है। इसमें 553 करोड़ 85 लाख रुपये वेतन, कार्यालय संचालन और अन्य खर्चों के लिए हैं, जबकि 20 करोड़ रुपये विभाग की संपत्तियों के रखरखाव पर खर्च होंगे। यह राशि 2026 से 2031 की अवधि के लिए है।

जबलपुर के जनजातीय संग्रहालय में एक नया पद

जबलपुर स्थित राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के बेहतर संचालन के लिए सहायक अनुसंधान अधिकारी का एक नियमित पद मंजूर किया गया है। इस पद पर नियुक्त अधिकारी संग्रहालय की देखरेख, प्रशासनिक कामकाज और दूसरे विभागों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके संचालन और रखरखाव पर सालाना 83 लाख 18 हजार रुपये खर्च होंगे।

पुलिस ने की कार्रवाई

इंडिया ब्लॉक की रैली के बाद 22 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर



एजेन्सी, नई दिल्ली

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की रैली के बाद पुलिस ने 22 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन प्रदर्शनकारियों को रविवार को रामलीला मैदान से जंतर-मंतर की ओर मार्च निकालने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया था। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित अनुमति के दायरे से बाहर जाकर मार्च निकालने का प्रयास किया था।

दरअसल, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रामलीला मैदान में रैली आयोजित की थी। इस दौरान चुनाव आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध जताया गया। पुलिस के अनुसार, रैली के आयोजन के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन वहां से जंतर-मंतर की ओर मार्च निकालने की अनुमति नहीं थी। पुलिस के मुताबिक, रैली में करीब 50 हजार लोगों के शामिल होने का अनुमान था। शाम करीब 5 बजे दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया (आरडब्ल्यूपीआई) के सदस्यों ने जंतर-मंतर की ओर मार्च निकालने की कोशिश की। इस दौरान दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने मिंटो रोड पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया।

पुलिस ने मौके से 22 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। हिरासत में लिए गए लोगों को दो बसों में बिठाकर द्वारका सेक्टर-23 और जाफरपुर कलां थाने ले जाया गया।

21 हजार करोड़ की पुणे मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन

पहले गरीबी खत्म करने के वादे होते थे अब जमीनी स्तर पर काम हो रहा: मोदी

एजेन्सी, नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई पीढ़ियों ने गरीबी खत्म करने के वादे सुने हैं। पहले गरीबी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नारों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे खत्म करने के लिए जमीन पर काम हो रहा है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने पुणे मेट्रो की करीब 21,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।

10-12 साल में भारत के 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए

आज दुनिया में भारत की चर्चा दो और वजहों से हो रही है। पहली, दुनिया में मुश्किल हालात के बावजूद भारत सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाला देश बना हुआ है। दूसरी, सिर्फ 10 से 12 साल में भारत के 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है।

महाराष्ट्र में खराब मौसम से कई किसान परेशान हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में जल संरक्षण के लिए काम हुआ है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से किसानों को नुकसान हुआ है। इस मुश्किल समय में NDA सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी।



देश के सैकड़ों छोटे शहरों को भी विकास के केंद्र के रूप में तैयार करना होगा। इसी सोच के साथ इस साल फरवरी में अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार इस फंड के लिए 1 लाख करोड़ की मदद दे रही है।

पुणे मेट्रो लाइन का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से हुआ है। यह विकास का ऐसा मॉडल है, जिसकी सफलता से देश की तरक्की को और रफ्तार मिलेगी।

पुणे मेट्रो के विस्तार से लोगों का समय बच रहा है और सफर आसान हो रहा है। जब किसी शहर में लोगों का समय बचता है, तो वहां काम करने की क्षमता बढ़ती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। अर्थव्यवस्था बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग, दोनों को लाभ मिलता है।

पुणे मेट्रो की लाइन-3 करीब 23 किलोमीटर लंबी है

पुणे मेट्रो की लाइन-3 यानी पिंक लाइन करीब 23 किलोमीटर लंबी है। यह मान से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक जाती है। इससे हिंजवड़ी IT हब और शिवाजीनगर के बीच मेट्रो सेवा शुरू होगी। इससे हजारों कछ कर्मचारियों और दूसरे यात्रियों को आने-जाने में आसानी होगी।

पीएम ने पुणे मेट्रो के दूसरे फेज की आधारशिला भी रखी। इस पर करीब 13,500 करोड़ खर्च होंगे। इसमें मेट्रो की लाइन 2A, 2B, 4 और 4A बनाई जाएंगी। इनके शुरू होने से शहर के रिहायशी, व्यावसायिक और कछ इलाकों के बीच सफर आसान होगा।

SIR में 30 राज्यों के 13 करोड़ नाम कटे

नाम ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं, फॉर्म 6 भरें, केस नहीं होगा: चुनाव आयोग



एजेन्सी, नई दिल्ली

अगर आपका नाम SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग ने कहा चाहे आप 10 साल से वोटर रहे हों, फिर भी फॉर्म-6 ही भरना होगा। इसको झूठा शपथ पत्र नहीं माना जाएगा, न ही कोई केस होगा।

यह फैसला उनके लिए मददगार होगा, जिनका नाम SIR के दौरान काट दिया गया। दरअसल, फॉर्म 6 में लिखना पड़ता है कि मेरा नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है।

कानूनी पेंच की वजह से फॉर्म-6 पर सेक्शन 31 के तहत लिखा होता है - गलत जानकारी दी तो 1 साल तक की सजा। लोग सोच रहे थे - हम तो पुराने वोटर हैं, पहली बार वाला कॉलम टिक करेंगे तो केस हो जाएगा। इस डर से लाखों लोग फॉर्म नहीं भर रहे थे। चुनाव आयोग ने कहा कि ये डर निकाल दीजिए, हम इसे फॉल्स डिक्लरेशन नहीं मानेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 2025-26 में बिहार, दिल्ली समेत 30 राज्यों में 13 करोड़ से ज्यादा नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए। दिल्ली में ही 1.45 करोड़ में से 47 लाख नाम हट गए।

चुनाव आयोग ने माना कि कई लोगों को डर था कि फॉर्म 6 में लिखना पड़ता है कि मेरा नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। ऐसे में पहले से रजिस्टर वोटर को लगता था कि ये झूठा शपथ पत्र होगा और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत उन पर झूठा बयान देने का केस चल सकता है। इसी वजह से लोग फॉर्म 6 भरने से हिचक रहे थे।

बरेली में विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, बोले....

'जीते तो होशियार, हारे तो चुनाव आयोग पर सवाल'

एजेन्सी, बरेली

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर चुनाव आयोग और ईवीएम की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनाव हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग को बदनाम करने लगते हैं। चुनाव जीतने पर अपनी योग्यता का दावा करते हैं और हारने पर व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र देश के नागरिक चलाएंगे, घुसपैठिए नहीं। घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होने वालों को जनता नकार देगी। वह मंगलवार को बरेली में ह्यलोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओह्न पदयात्रा के दौरान आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे।

जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों की मेहनत से अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता चुनाव आयोग के प्रति लोगों के विश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने गुजरात के गिर के जंगल में एक मतदाता का वोट डलवाने के लिए दस कर्मचारियों को दस किलोमीटर पैदल भेजा। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में एक मतदाता तक पहुंचने के लिए कर्मचारियों ने पहाड़ों में 44 किलोमीटर का सफर किया। चुनाव आयोग की यही व्यवस्था है कि मतदाता को आयोग के दरवाजे पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आयोग उसके दरवाजे तक पहुंचेगा।



विकसित भारत के लिए एनडीए को मजबूत करने का आह्वान

नड्डा ने कहा कि विपक्ष को चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने के बजाय जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के तमिलनाडु में 58 साल, पश्चिम बंगाल में 48 साल, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 35 साल से सत्ता से बाहर रहने का जिक्र किया। इसके विपरीत उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने तथा उत्तर प्रदेश में दो बार लगातार सरकार बनने का उल्लेख किया।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का समर्थन करते हुए नड्डा ने कहा कि देश में यह प्रक्रिया 12 बार हो चुकी है। इनमें दस बार कांग्रेस और दो बार एनडीए के शासनकाल में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2004 में इसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह प्रक्रिया हो रही है। उन्होंने दावा किया कि 10.24 लाख बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की भागीदारी से प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने कहा कि 96 करोड़ मतदाताओं की सूची के पुनरीक्षण में 13 करोड़ नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उनके मुताबिक इसमें तीन करोड़ अनुपस्थित, छह करोड़ 30 लाख स्थानांतरित, एक करोड़ दोहरी प्रविष्टि वाले और 2.80 करोड़ मृत मतदाताओं के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का दो जगह वोट नहीं हो सकता।

नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से सटे नौ जिलों में वर्ष 2004 से 2024 के बीच मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का दावा किया। उन्होंने उत्तर दिनाजपुर में 105 प्रतिशत, मालदा में 94 प्रतिशत, मुर्शिदाबाद में 87 प्रतिशत, दक्षिण 24 परगना में 83 प्रतिशत और जलपाईगुड़ी में 82 प्रतिशत वृद्धि का आंकड़ा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के कारण मतदाता संख्या बढ़ी है। हालांकि ये आंकड़े और वृद्धि के कारणों को लेकर उनके दावे थे।

इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन उनकी दादी इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान करीब 1.30 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भी आपातकाल के दौरान दो बार कक्षा से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कांग्रेस पर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सरदार पटेल के बजाय जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के घटनाक्रम को भी उन्होंने वोट चोरी से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा।

आने वाले वर्ष के लिए नई उम्मीदों, नई ऊर्जा और मंगलमय भविष्य की सामूहिक कामना का प्रतीक बना

2027 दीपों की रोशनी से जगमगाया गौहर महल का दीवान-ए-खास, दीपोत्सव ने रचा अनुपम दृश्य

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

भोपाल। ऐतिहासिक गौहर महल मंगलवार की शाम दीपों की स्वर्णिम आभा से आलोकित हो उठा। मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की ओर से आयोजित दीपोत्सव मेले में शाम ठीक 6:15 बजे 2027 दीप प्रज्ज्वलित किए गए।

एक साथ प्रज्ज्वलित हुए दीपों की सुनहरी रोशनी ने महल के दीवान-ए-खास को ऐसा अलौकिक स्वरूप प्रदान किया कि पूरा परिसर प्रकाश, उल्लास और सांस्कृतिक आभा से सराबोर हो गया। यह आयोजन वर्ष 2026 की विदाई बेला और नववर्ष 2027 के स्वागत की भावनाओं को समर्पित रहा।



दीपों की कतारों ने ऐतिहासिक स्थापत्य की खूबसूरती में नई चमक भर दी। महल की प्राचीन दीवारों, मेहराबों और पारंपरिक वास्तुशिल्प के बीच जलते दीपों का दृश्य भारतीय संस्कृति की उस सनातन परंपरा का स्मरण करा रहा था, जिसमें दीप केवल रोशनी का माध्यम नहीं, बल्कि आशा, सकारात्मकता, ज्ञान और मंगलकामना के प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही विशेष रूप में विकसित मध्यप्रदेश की थीम पर दीये सजाये गए। इस अवसर पर उमेश श्रीवास्तव, उप संचालक हथकरघा, लेखपाल रमेश शाक्य, मिलिंद मेंडी सहायक प्रबंधक, प्रबंधक रंजना निनावे, आलोक भावसार, सुरेंद्र वर्मा, रमाकांत अग्रवाल। रंगोली कार्यकर्ता सुमन कोल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। दीपों की लौ में झलकी परंपरा और संस्कृति दीवान-ए-खास में सजे दीपों की श्रृंखला ने अतीत और वर्तमान के बीच एक सुंदर सांस्कृतिक सेतु निर्मित किया। मिट्टी के दीपों से निकलती लौ ने स्वदेशी शिल्प और स्थानीय कारीगरों की रचनात्मकता को भी विशेष अभिव्यक्ति दी। दीपोत्सव मेले का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प, माटीकला और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने के साथ भारतीय उत्सव परंपराओं को जीवंत बनाए रखना है।



इस आयोजन में 2027 दीपों का प्रज्ज्वलन केवल एक प्रतीकात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि आने वाले वर्ष के लिए नई उम्मीदों, नई ऊर्जा और मंगलमय भविष्य की सामूहिक कामना का प्रतीक बना। ऐतिहासिक गौहर महल में साकार हुआ यह दीपोत्सवी दृश्य शहर की सांस्कृतिक स्मृतियों में एक सुंदर अध्याय जोड़ गया। 2026 को विदाई देते दीपों की लौ ने मानो संदेश दिया कि समय बदलता है, वर्ष गुजरते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपराओं का प्रकाश सदैव अक्षुण्ण रहता है।

एनआईटी में चयन पर टीटीई की पुत्री को ?40 हजार का लैपटॉप प्रदान किया

केंद्रीय कर्मचारी हित निधि के माध्यम से मेधावी छात्राओं को शिक्षा के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

रेल कर्मचारियों के परिवारों की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेल द्वारा केंद्रीय कर्मचारी हित निधि के माध्यम से एक सराहनीय पहल की गई है। इसी क्रम में इटारसी में कार्यरत टीटीई श्री प्रमोद कुमार चौरसिया की सुपुत्री कु. आसिता चौरसिया का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चयन होने पर उन्हें ?40,000 मूल्य का लैपटॉप प्रदान किया गया। केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समिति की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, वर्ष 2026-27 में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली पात्र रेल कर्मचारियों की पुत्रियों को लैपटॉप प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है।



इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के दौरान डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना तथा उनकी शैक्षणिक प्रगति को सहयोग देना है। कार्यक्रम में सहायक कार्मिक अधिकारी (कल्याण) श्री वाई.बी. गुप्ता, कल्याण निरीक्षक श्री मधुर सुनहरे, जोनल केंद्रीय कर्मचारी हित निधि सदस्य श्री संतोष चतुर्वेदी एवं मंडल कर्मचारी हित निधि सदस्य श्री तरुण शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह पहल रेल कर्मचारियों के परिवारों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कर्मचारी कल्याण के प्रति रेल प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चयन हासिल कर टीटीई की पुत्री ने परिवार का नाम रोशन किया है। छात्रा की इस उपलब्धि पर उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 40 हजार रुपए कीमत का लैपटॉप प्रदान किया गया। इस अवसर पर छात्रा की सफलता की सराहना करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। प्रतिष्ठित संस्थान में चयन होना किसी भी विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसके लिए निरंतर मेहनत, लगन और पढ़ाई के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। टीटीई की पुत्री ने अपनी मेहनत के दम पर यह सफलता हासिल की। उसकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। छात्रा को प्रदान किया गया लैपटॉप उसकी आगे की पढ़ाई में उपयोगी साबित होगा।

वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा और उच्च अध्ययन के लिए लैपटॉप एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और विभिन्न तकनीकी विषयों से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रा की शैक्षणिक उपलब्धि को सम्मान देना और उसे आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। 40 हजार रुपए का लैपटॉप मिलने से छात्रा को हढ्ढञ्ज में पढ़ाई के दौरान तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता में मदद मिलेगी। छात्रा की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। यह उपलब्धि बताती है कि मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं।

जनसुनवाई में अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं, जनसुनवाई में 116 आवेदन प्राप्त हुए



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

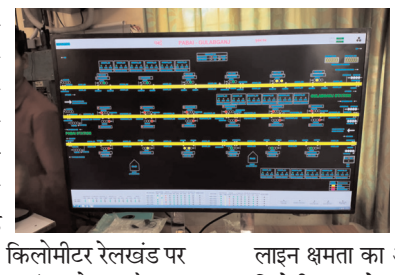
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में एडीएम श्री पी.सी. शाक्य, श्री महेन्द्र कबचे ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से 116 आवेदन प्राप्त हुए। इस मौके पर एसडीएम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनसुनवाई में आए दिव्यांग श्री रमेश प्रसाद जो कि पैरों से 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं, को जन सुनवाई में अपर कलेक्टर श्री महेन्द्र कबचे एवं डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा ट्राय साइकिल प्रदान की गई।

एडीएम श्री शाक्य, श्री कबचे ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बीना-गुलाबगंज रेलखंड में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं प्रभावी बनाने की दिशा में पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल द्वारा बीना-भोपाल रेलखंड पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में बीना से गुलाबगंज स्टेशनों के मध्य यह कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अंतर्गत गंजबासौदा-पबई-गुलाबगंज रेलखंड पर 03 नवंबर 2026 को दोपहर 13:30 बजे स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली चालू कर दी गई। बीना से भोपाल के बीच कुल 138 किलोमीटर लंबे रेलखंड में से बीना-गुलाबगंज के बीच 64 किलोमीटर रेलखंड पर यह कार्य पूरा हो चुका है। शेष गुलाबगंज-भोपाल के 74 किलोमीटर रेलखंड में कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गंजबासौदा-पबई-गुलाबगंज रेलखंड पर कुल 18.24 रूट किलोमीटर (दोहरी लाइन में 36.48 किलोमीटर) पर आधुनिक सिग्नलिंग व्यवस्था स्थापित की गई है। इसमें 44 ऑटो सिग्नल एवं 204 डिटेक्शन पॉइंट स्थापित किए गए हैं। इस कार्य की प्रमुख विशेषताओं में डायरेक्ट ड्राइव स्प्रूव 10, ब्लॉक सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग के लिए रिले कैबिनेट, सिमेंस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ी निगरानी तथा स्टेशन मास्टर कक्ष में माध्यम से ऑटो सिग्नलिंग की जानकारी प्रदर्शित करने की व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त 24 फाइबर ऑप्टिक रिंग पथ, ड्यूल एक्सल काउंटरतथा पूरे रेलखंड में 4 48 फाइबर केबल बिछाई गई है। स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली से ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने, रेल परिचालन की निगरानी को बेहतर बनाने तथा उपलब्ध रेल लाइन क्षमता का अधिक कुशल उपयोग करने में सहायता मिलेगी। इससे भोपाल-बीना रेलखंड पर आधुनिक सिग्नलिंग तकनीक के विस्तार के साथ रेल परिचालन की संरक्षा एवं दक्षता को और मजबूती मिलेगी। यह कार्य मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर, कोटा श्री सचिन शुक्ला की देखरेख में पूरा किया गया।



स्वामित्व योजना से हितग्राही उमेश को सम्पत्ति का मिला कानूनी अधिकार

दूर हुई चिंता रजिस्ट्री मिलने से बढ़ा भरोसा, अब अपनी संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर निश्चिंत हैं उमेश

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

सरकार की स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को उनकी आवासीय सम्पत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। योजना के माध्यम से हितग्राहियों को उनकी सम्पत्ति का अधिकार अभिलेख एवं रजिस्ट्री मिलने से न केवल उनकी सम्पत्ति सुरक्षित हो रही है, बल्कि वर्षों से चली आ रही चिंताएं भी दूर हो रही हैं। भोपाल संभाग के रायसेन जिले के बेगमगंज विकासखण्ड की मरखेड़ा टप्पा ग्राम पंचायत में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शिविर में कलेक्टर द्वारा हितग्राही श्री उमेश सेन को स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री प्रदान की गई। रजिस्ट्री प्राप्त होने से हितग्राही उमेश को भी बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए हितग्राही उमेश बताते हैं कि उनके परिवार में सात सदस्य है तथा खेती-बाड़ी ही उनकी आय का जरिया है। योजना के तहत उन्हें अपनी सम्पत्ति की रजिस्ट्री मिलने से उसके स्वामित्व को लेकर अधिक विश्वास और सुरक्षा का एहसास हो रहा है। सम्पत्ति का वैध दस्तावेज मिलने से उनके मन की चिंता दूर हुई है और भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ा है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध हो रहा है, जिससे सम्पत्ति संबंधी विवादों की आशंका कम करने और जरूरत के समय दस्तावेजों के उपयोग में भी सहायता मिलती है। स्वामित्व योजना ग्रामीण नागरिकों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान कर उन्हें अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।



14 नवंबर को भोपाल में होगा भव्य सहस्त्रदीपोत्सव, 10 हजार दीपों से जगमगाएगा कोलार का सहस्त्रबाहु ब्रिज

भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव पर एकता, संस्कार और सेवा की ज्योति प्रज्वलित करें

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

भगवान श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन के जन्मोत्सव को सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गौरव और सेवा के संकल्प के साथ यादगार बनाने के लिए कलचुरी सेना परिवार द्वारा 14 नवंबर 2026, शनिवार को भोपाल में भव्य सहस्त्रदीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कोलार रोड स्थित जेके अस्पताल के सामने भगवान श्री सहस्त्रबाहु ब्रिज को 10 हजार दीपों की रोशनी से जगमगाने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन शाम 6 बजे से प्रारंभ होगा। कलचुरी सेना ने भोपाल सहित आसपास के क्षेत्रों के समस्त समाजबंधुओं से सपरिवार शामिल होकर भगवान सहस्त्रबाहु के नाम एक दीप प्रज्वलित करने की भावपूर्ण अपील की है। यह आयोजन केवल दीप जलाने का धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की एकजुटता, सामूहिक सहभागिता और आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली परंपरा से जोड़ने का अवसर है। आयोजकों का प्रयास है कि इस दिन समाज का प्रत्येक परिवार अपनी उपस्थिति और अपने दीप के माध्यम से यह संदेश दे कि जब समाज एक साथ खड़ा होता है, तो उसकी सामूहिक शक्ति हजारों दीपों की तरह प्रकाश फैलाती है। कलचुरी सेना मध्यप्रदेश के संगठन प्रभारी वीरसिंह राय एवं कार्यक्रम संयोजक राजेश राय ने बताया कि आयोजन समिति ने समाज के प्रत्येक परिवार से 21 घी के दीपक, तेल और बाती लेकर पहुंचने का आग्रह किया है। परिवारों से की गई यह अपील केवल दीपों की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी और अपने सांस्कृतिक गौरव के प्रति जिम्मेदारी का भाव जुड़ा है। बच्चों से लेकर युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठजनों तक सभी की सहभागिता से यह आयोजन सामूहिक उत्सव का स्वरूप लेगा। उन्होंने



कहा कि भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव पर प्रज्वलित होने वाला प्रत्येक दीप समाज की एकता, आत्मसम्मान और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बनेगा। इसलिए समाजबंधु इस अवसर को केवल देखने का नहीं, बल्कि स्वयं सहभागी बनने का पर्व मानें और अपने परिवार के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचें। पूजा-अर्चना, आरती के बाद होगा समाजसेवियों और प्रतिभाओं का सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री सहस्त्रार्जुन की पूजा-अर्चना, आरती और जयघोष के साथ होगा। इसके बाद समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाजसेवियों तथा प्रतिभावान युवाओं का सम्मान किया जाएगा। आयोजन के माध्यम से समाज में सेवा, सहयोग, शिक्षा, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। कलचुरी सेना के अध्यक्ष कौशल राय ने कहा कि सहस्त्रदीपोत्सव को केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि समाज जागरण और संगठन शक्ति के उत्सव के रूप में देखा जाना चाहिए। सहस्त्रबाहु ब्रिज पर हजारों दीपों की रोशनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता से जुड़ने की प्रेरणा देगी। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल महापौर मालती राय एवं भाजपा प्रदेश मंत्री सुश्री राजो मालवीय शामिल होंगी। कलचुरी सेना परिवार ने समाज के प्रत्येक परिवार, युवा, महिला, वरिष्ठजन और सामाजिक संगठनों से आग्रह किया है कि भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव पर आयोजित इस महोत्सव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। परिवार के साथ पहुंचकर दीप प्रज्वलित करना केवल परंपरा का निर्वहन नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने जुड़ाव और जिम्मेदारी को अभिव्यक्त करने का अवसर है। आयोजकों का कहना है कि जब हजारों परिवार एक साथ दीप जलाएंगे, तब सहस्त्रबाहु ब्रिज की रोशनी के साथ समाज की एकता का संदेश भी दूर तक पहुंचेगा।

जबलपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने टीआई की मौत पर दुख जताते हुए दिया भरोसा

मुख्यमंत्री ने किया डॉ. ए.के. द्विवेदी की पुस्तक 'आधुनिक एनीमिया विज्ञान' का विमोचन

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर



होम्यौपैथी संकाय के बोर्ड ऑफ स्टडी के सदस्य डॉ. द्विवेदी की पुस्तक में एनीमिया के समग्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनस्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से किया गया है प्रकाश, मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। होम्यौपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, केंद्रीय होम्यौपैथी अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य और मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में होम्यौपैथी संकाय के अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडी के सदस्य डॉ. ए.के. द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक 'आधुनिक एनीमिया विज्ञान : समग्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण' का विमोचन गत दिवस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक गरिमामय समारोह में किया। विमोचन के उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुस्तक का अवलोकन किया और एनीमिया जैसे गंभीर एवं महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य विषय पर डॉ. द्विवेदी के लेखन तथा जनजागरूकता संबंधी निरंतर प्रयासों की गहरी सराहना की। इस अवसर पर पुस्तक के सह-लेखक डॉ. अथर्व द्विवेदी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुस्तक के निर्माण में डॉ. अथर्व द्विवेदी के साथ अन्य सह-लेखकों का भी महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा है। आधुनिक चिकित्सा और पोषण के व्यापक संदर्भ पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण पुस्तक में एनीमिया को केवल एक बीमारी के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और जनजागरूकता के व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करने का गंभीर प्रयास किया गया है। पुस्तक के माध्यम से पाठकों को एनीमिया के कारणों, निदान, आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और इससे बचाव के वैज्ञानिक उपायों की विस्तृत जानकारी मिलेगी, जो चिकित्सकीय जगत के साथ-साथ आम जनता के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होगी। एनीमिया के खिलाफ लंबे समय से सक्रिय हैं डॉ. द्विवेदी डॉ. ए.के. द्विवेदी लंबे समय से प्रदेश और देश में एनीमिया के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियानों, स्वास्थ्य शिविरों, निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच, पोषण जागरूकता कार्यक्रमों और विशेष व्याख्यानों के माध्यम से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। उनका यह साहित्यिक एवं चिकित्सीय प्रयास समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश को लारा परियोजना से मिलेगी 800 मेगावाट किफायती बिजली



■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्यप्रदेश में भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और प्रदेशवासियों को सस्ती व निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में ऊर्जा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। एनटीपीसी की छत्तीसगढ़ स्थित लारा चरण-III परियोजना से विद्युत क्रय के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और एनटीपीसी के बीच विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत मध्यप्रदेश को लारा परियोजना से 800 मेगावाट किफायती बिजली प्राप्त होगी। वर्ष 2031-32 तक इस संयंत्र से प्रदेश को उचित दरों पर विश्वसनीय बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अनुबंध के अनुसार लारा-परियोजना से मध्यप्रदेश को लगभग 4.97 रुपये प्रति यूनिट की अनुमानित दर पर बिजली उपलब्ध होगी। कृषि और उद्योगों को मिलेगा फायदा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रमुख सचिव ऊर्जा मनीष सिंह और ऊर्जा सचिव व एमपी Power Management Company के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले की उपस्थिति में यह अनुबंध हुआ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि राज्य सरकार हर उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती बिजली देने के लिए संकल्पित है। यह अनुबंध भविष्य में राज्य के कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। कैप्टिव खदान से कम होगी लागत लारा परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संयंत्र कोयला खदान के बेहद पास स्थित है और इसे एनटीपीसी की अपनी कैप्टिव खदान से कोयला प्राप्त होता है। कोयले की सीधी और सुरक्षित उपलब्धता से परिवहन खर्च में भारी बचत होगी, जिससे बिजली की आपूर्ति पूरी तरह विश्वसनीय और न्यूनतम लागत पर संभव हो सकेगी। इस अवसर पर एनटीपीसी दिल्ली से मुख्य महाप्रबंधक कॉमर्शियल ए.एस. पांडे, महाप्रबंधक संदेश जायसवाल, रायपुर से अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक कॉमर्शियल भूपेश कुमार और एमपीपीएमसीएल की ओर से मुख्य महाप्रबंधक कॉमर्शियल डॉ. आर.बी. सक्सेना उपस्थित रहे।

पंजाबी हिन्दू एसोसियेशन में ग्रोवर अध्यक्ष व ओबेराय सचिव बने



■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

पंजाबी हिन्दू एसोसियेशन के संपन्न चुनाव में नरेश ग्रोवर अध्यक्ष और डॉ.राजीव ओबेराय सचिव निर्वाचित हुये। इनका प्रस्ताव पूर्व वित्त मंत्री तरूण भानोट द्वारा रखा गया था। मीडिया प्रभारी उमेश शर्मा ने बताया कि 2026-28 की नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया जिसमें प्रमोद मरवाहा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पंकज सेठी उपाध्यक्ष, भारत कुमार कपूर सहसचिव, दीपक वर्मा सहसचिव, सुशील आनंद कोषाध्यक्ष, उमेश शर्मा (पप्पू) जनसंपर्क अधिकारी, सुधीर मेहता आंतरिक लेखा परीक्षक एवं कार्यकारिणी सदस्य तरूण भानोत, इंदर कुमार विरमानी, रघुवर कुमार कपूर, धनवंतराय सेठी, डॉ. सुनील बहल, गुलशन माखीजा, उमेश खुराना, नरेन्द्र धमीजा, नीरज ब्योत्रा, संजय अरोरा, प्रदीप वाधवा, संजीव मलिक, मनमोहन कोचर, अजीत मिनोचा, दीपक चंडोक, संदीप सेठी नियुक्त किये गये।

कृषिविवि कुलपति पद पर बने रहने को चुनौती, शासन और राजभवन को हाईकोर्ट का नोटिस, जवाब तलब

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी) के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की नियुक्ति और उनके पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश शासन और राजभवन सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी अनावेदकों को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में कुलपति की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित होने का हवाला देते हुए सवाल उठाया गया है कि निर्धारित आयु पूरी करने के बाद भी डॉ. मिश्रा किस आधार पर पद पर बने हुए हैं। जबलपुर निवासी डॉ. सत्येंद्र यादव ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट याचिका दायर कर उनकी नियुक्ति और पद पर बने रहने की वैधानिकता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय रायजादा के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों में कुलपति पद पर बने रहने की अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित है। याचिका के मुताबिक डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की जन्मतिथि 1 जुलाई 1956 है। उन्हें 17 नवंबर 2022 को जेएनकेवीवी का कुलपति नियुक्त किया गया था। इस हिसाब से उन्होंने 30 जून 2026 को 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इसके बावजूद उनके पद पर बने रहने को यूजीसी के नियमों के विपरीत बताया गया है। याचिका में राज्यपाल कार्यालय द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति के समय 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी बनाम रवींद्र जुगरान और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनिंद्य सुंदर दास का हवाला देते हुए यूजीसी के नियमों की अनिवार्यता का तर्क दिया गया है। याचिकाकर्ता ने डॉ. मिश्रा को कुलपति पद से हटाने, 70 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पद पर बने रहने को अवैध घोषित करने और राज्य शासन तथा राजभवन को नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देने की मांग की है। अंतरिम राहत के तौर पर डॉ. मिश्रा को कुलपति के रूप में कार्य करने और किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से रोकने का आग्रह भी किया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका पर अनावेदकों से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई जवाब प्रस्तुत होने के बाद होगी।

पमरे में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन



■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

पश्चिम मध्य रेल प्रशासन द्वारा रेल पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए 1 से 30 नवंबर 2026 तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाया जा रहा है। इन शिविरों में पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का लाइव डेमो एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। आधार आधारित डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से पेंशनर घर बैठे अथवा नजदीकी शिविर में अपना जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उमंग सामुदायिक भवन जबलपुर, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित समाधान केंद्र, कटनी एवं सतना समाधान केंद्र तथा नरसिंहपुर, ब्यौहारी, दमोह, सागर एवं पिपरिया के स्टेशन अधीक्षक कार्यालयों में कार्यदिवसों पर प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार ने पार्वती कोल को तत्काल 4 लाख रूपये सहायता राशि स्वीकृत की

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

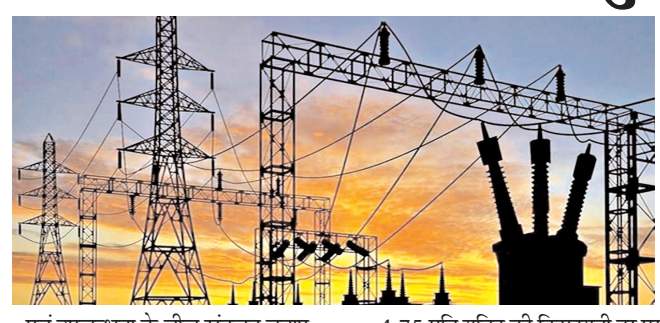


कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने जनसुनवाई में पहुंची सिहोरा के वार्ड नंबर 01 निवासी आवेदिका पार्वती कोल को उनके पति स्व. कमलेश कोल की 29 जनवरी 2026 को मुहारी डेम में डूबने से हुई अकाल मृत्यु पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम ग्रामीण को निर्देश दिए कि उन्हें नियमानुसार अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाए। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम ग्रामीण ने राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के प्रावधानों के तहत मृतक के परिवार को चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत कर दी है, जिससे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि अनुग्रह राशि के स्वीकृति पत्र पीड़ित परिवार के घर जाकर प्रदाय करें।

बिजली एनटीपीसी के माध्यम से मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराई जाएगी

रबी सीजन में 250 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होगी

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर



मध्यप्रदेश में रबी सीजन के दौरान विद्युत की बढ़ती मांग एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को ईस्टर्न रीजन अनअलोकेटेड पावर पूल से 250 मेगावाट विद्युत आवंटित की गई है। यह बिजली एनटीपीसी के माध्यम से मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसका आवंटन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। रबी सीजन में कृषि कार्यों एवं अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आवंटन प्रदेश में विद्युत मांग एवं उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को अतिरिक्त संबल मिलेगा तथा मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि उक्त विद्युत लगभग 4.75 प्रति यूनिट की किफायती दर पर उपलब्ध होगी। इससे प्रदेश को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर अतिरिक्त विद्युत प्राप्त करने में मदद मिलेगी तथा विद्युत क्रय की लागत को नियंत्रित रखने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा इस संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को आवश्यक कार्रवाई करते हुए आवंटन को तत्काल प्रभाव से लागू करने तथा संबंधित पक्षों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। आवंटित विद्युत के उपयोग हेतु आवश्यक विद्युत क्रय अनुबंध एवं अन्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी की जाएंगी। मध्यप्रदेश शासन प्रदेश के सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को मांग के अनुरूप विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रबी सीजन में एनटीपीसी के माध्यम से 250 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की उपलब्धता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

ऊर्जा मंत्री द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की हिंदी एवं अंग्रेजी पत्रिका 'विद्युत ब्रह्मेति' तथा 'वेतन मित्र' का विमोचन

कर्मचारी सुविधा एवं कंपनी की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

■ एक सत बुलेटिन, गोटेगांव।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंगलवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की विभागीय कॉर्पोरेट पत्रिका *विद्युत ब्रह्मेति' के अक्टूबर 2026 के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों* का विमोचन किया । इस अवसर पर कंपनी द्वारा तैयार की गई महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तिका *वेतन मित्र' * का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनीष सिंह एवं ऊर्जा सचिव श्री विशेष गढ़पाले उपस्थित थे। कंपनी की पत्रिका 'विद्युत ब्रह्मेति' के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की उपलब्धियों, नवाचारों, तकनीकी प्रगति, उपभोक्ता सेवाओं, विभागीय गतिविधियों एवं कंपनी की महत्वपूर्ण पहलों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। पत्रिका का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभ करने का उद्देश्य कंपनी की उपलब्धियों, नवाचारों एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों, पावर यूटिलिटीज एवं राष्ट्रीय स्तर के पाठकों तक पहुंचाना है। इससे कंपनी की पहचान एवं ब्रांड छवि को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी। इसी क्रम में विमोचित 'वेतन मित्र' * में वर्ष 1984 से वर्तमान समय तक वेतन एवं भत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण परिपत्रों का संकलन किया गया है। यह संकलन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए भी एक उपयोगी संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। वेतन एवं भत्तों से संबंधित किसी भी प्रावधान अथवा पुराने परिपत्र की जानकारी प्राप्त करने में यह पुस्तक सहायक सिद्ध होगी।उल्लेखनीय है कि कंपनी में संस्थागत ज्ञान के संरक्षण, दस्तावेजों के सुव्यवस्थित संकलन एवं कार्मिकों को आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व में भी 'स्थापना मित्र' भाग-1 एवं भाग-2, 'पेंशन मित्र' तथा 'नीति मित्र' * जैसी महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तिकाएं तैयार की जा चुकी हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 'वेतन मित्र' का प्रकाशन कंपनी की ज्ञान प्रबंधन एवं कर्मचारी सुविधा संबंधी प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस दौरान मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी श्री घनश्याम प्रसाद पाण्डेय उपस्थित रहे।



संपादकीय

क्या संसद अवैध है?

राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के 21 दलों की साझा वोट चोरी रैली सफल रही अथवा नहीं रही, हम इस पचड़े में फंसना नहीं चाहते, लेकिन देश भर में एक संदेश देने में विपक्ष जरूर सफल रहा है। यह संदेश है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाया जाएगा और उन्हें जेल में भेजा जाएगा। यह तभी संभव होगा, जब ज्ञानेश अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दें अथवा संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए। फिलहाल दोनों ही स्थितियां संभव नहीं लगतीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि वे वोट चोरी की आपराधिक साजिश में संलिप्त रहे हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह भी तभी संभव होगा, जब केंद्र में विपक्ष के इंडी गठबंधन की सरकार होगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। सर्वोच्च अदालत भी कानूनी कार्रवाई पर फैसला दे चुकी होगी! फिलहाल इसके भी आसार नहीं हैं, बेशक विपक्ष कितनी भी हुंकारें भरता रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे के ये कथन सवालिया और गलत हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था।

मतदाता सूचियों से 13.5 करोड़ नाम काट दिए गए। करीब 15 फीसदी मतदाताओं के नाम काट दिए गए। हर 7 में से 1 मतदाता का नाम हटा दिया गया, जबकि जीत-हार का अंतर मात्र 3 फीसदी था। राहुल गांधी ने यह गलत बोला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19-20 फीसदी वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 38 फीसदी से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला था। कांग्रेस के 99 सांसदों और अकेली भाजपा के 240 सांसदों की संख्या के बीच बहुत बड़ा फासला है। यदि 2024 का संसदीय चुनाव अवैध था, तो सिर्फ प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भाजपा सांसदों के ही चुनाव अवैध नहीं थे, बल्कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसदों के निर्वाचन भी अवैध हैं। लोकसभा के समूचे 543 सांसदों के चुनाव भी अवैध हैं। क्या भारत जैसे लोकतंत्र और संवैधानिक देश में अवैध संसद काम कर सकती है? क्या नेता प्रतिपक्ष का यह कथन देश के मतदाताओं, जनादेश, लोकतंत्र और संविधान का मजाक नहीं उड़ा रहा है?

दरअसल यह खास किस्म की उत्तेजना, तैश, आवेश और कुंठा में बोला गया कथन है। चुनाव आयोग ने 28 अक्तूबर, 2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अभियान बिहार से शुरू किया था, तो मई-जून, 2024 के लोकसभा चुनाव में किसने और कैसे वोट चोरी की? एसआईआर कर्नाटक, तेलंगाना, केरल में भी किया गया है, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। गौरतलब यह है कि जनवरी, 2024 में सहकारी सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता को 15 मार्च को, सुखबीर सिंह संधु के साथ, चुनाव आयुक्त के संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया था। तब राजीव कुमार सीईसी थे। यदि तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच सहमति न हो, तो कोई भी निर्णय लागू नहीं किया जा सकता। यही हालिया संकट और विवाद है। वोट चोरी तो बेहद गंभीर और साजिशाना हरकत है। बहरहाल विपक्ष की लगातार राजनीतिक मुहिम के बावजूद वोट चोरी एक राष्ट्रीय मुद्दा, आम आदमी के सरोकार का मुद्दा नहीं बन पाया है।

जिन 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनमें करीब 2.88 करोड़ नाम ऐसे हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं और 1 करोड़ से अधिक लोगों के पास दोहरे मतदाता पहचान पत्र हैं। यह अवैध और असंवैधानिक है। राजधानी दिल्ली में ही 47 लाख से अधिक के नाम अनिश्चित हैं। यदि वे आंदोलित होते, तो दिल्ली की सडकें अवरुद्ध हो जातीं। हिंसा भी भडक सकती थी! यदि उनमें से 2 लाख मतदाता भी विपक्ष की रैली के साथ जुड़ते, तो एक असामान्य भीड़ सडकों पर बिछ सकती थी! किसी भी सरकार के लिए वह स्थिति चुनौतीपूर्ण होती, लेकिन ऐसी चुनौती देश के किसी भी कोने से दिखाई नहीं दी है।

10 साल के मध्यप्रदेश में पहली बार किसानों के ज्ञान पर बरसे ऐसे पुरस्कार

ट्रैक्टर, बुलेट और स्कूटी डॉ. मोहन यादव की अनूठी पहल ने किसान पुत्रों का जीता दिल, वीर भारत न्यास ने रचा सम्मान का नया अध्याय

> आमतौर पर क्विज प्रतियोगिताओं का नाम आते ही स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं और पुरस्कारों की कल्पना सामने आती है। लेकिन खेती-किसानी में जुटे किसान और उनके परिवारों के युवा भी ज्ञान की ऐसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे, यह विचार अपने आप में अभिनव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाले वीर भारत न्यास ने किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत प्रदेश के किसानों के लिए ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की।

मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर एक ऐसी पहल सामने आई, जिसकी कल्पना शायद ही किसी किसान ने कभी की होगी। जिस सरकार से किसान अपनी फसल, सिंचाई, खाद-बीज और खेती की लागत से जुड़ी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा करता है, उसी सरकार की पहल पर अब किसान के ज्ञान को भी सम्मान मिल रहा है। वह भी ऐसा सम्मान, जिसमें पुरस्कार के रूप में ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल और ई-स्कूटी जैसे आकर्षक उपहार शामिल हैं। खेती-किसानी के लिए संघर्ष करने वाले किसान परिवारों के लिए यह केवल पुरस्कारों की घोषणा नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, प्रतिभा और स्वाभिमान को पहचान देने वाली पहल है। मध्यप्रदेश में अनेक मुख्यमंत्री हुए। किसानों के हितों की चिंता करने वाले नेतृत्व ने खेती-किसानी के लिए योजनाएं बनाईं, सुविधाएं दीं और उनके जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए। लेकिन किसानों के लिए एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करना, जिसमें भाग लेकर वे अपने ज्ञान के बल पर बड़े पुरस्कार जीतने का अवसर प्राप्त करें, निश्चित रूप से एक अलग सोच का परिचायक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दिशा में अपनी विशिष्ट पहल से ध्यान आकर्षित किया है।

किसान पुत्रों के लिए भी होगी क्विज, यह किसने सोचा था!

आमतौर पर क्विज प्रतियोगिताओं का नाम आते ही स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं और पुरस्कारों की कल्पना सामने आती है। लेकिन खेती-किसानी में जुटे किसान और उनके परिवारों के युवा भी ज्ञान की ऐसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे, यह विचार अपने आप में अभिनव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाले वीर भारत न्यास ने किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत प्रदेश के किसानों के लिए ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। इसका उद्देश्य किसानों को जानकारी और जागरूकता से जोड़ने के साथ उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना भी था। इस पहल ने किसान पुत्रों को यह अवसर दिया कि वे अपनी जानकारी परखें, प्रतियोगिता में भाग लें और अपनी प्रतिभा के बल पर सम्मान प्राप्त करें।

प्रतियोगिता में करीब 40 हजार किसानों ने हिस्सा लिया। 24 प्रश्नों की इस क्विज में 15,298 प्रतिभागियों ने पूरे अंक हासिल किए। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से 165 विजेताओं का चयन किया गया। इनमें 55 किसानों को ट्रैक्टर, 55 को बुलेट मोटरसाइकिल और 55 को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी।

पुरस्कार नहीं, किसान के आत्मविश्वास का सम्मान

जरा उस किसान परिवार की कल्पना कीजिए, जिसके लिए ट्रैक्टर खरीदना एक बड़ा आर्थिक निर्णय होता है। उस युवा की खुशी का अनुमान लगाइए, जिसे बुलेट या ई-स्कूटी जैसा पुरस्कार जीतने का अवसर मिलता है। उसके लिए यह सिर्फ एक वाहन प्राप्त करने की बात नहीं, बल्कि इस एहसास की बात भी है कि उसकी जानकारी और उसकी भागीदारी का भी मूल्य है।

यही इस पहल की सबसे बड़ी खूबी है। सरकारें अक्सर किसानों को लाभार्थी के रूप में देखती हैं, लेकिन यहां किसान को एक प्रतियोगी के रूप में सामने लाया गया है। उसे अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिला है और उसके ज्ञान को बड़े पुरस्कारों से जोड़कर प्रोत्साहित किया गया है। निश्चित रूप से, किसी भी प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने वाले सीमित होते हैं, लेकिन ऐसी पहल से पैदा होने वाला उत्साह कहीं अधिक व्यापक हो सकता है। प्रदेश के हजारों किसान इस प्रक्रिया से जुड़े। उन्होंने सवालों के जवाब दिए, अपनी जानकारी परखी और एक ऐसी गतिविधि का हिस्सा बने, जिसमें किसान स्वयं केंद्र में था।

मोहन यादव की सोच में क्यों दिखती है अलग बात?

डॉ. मोहन यादव की इस पहल का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इसमें महंगे पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसका महत्व इस बात में है कि खेती-किसानी को लेकर सरकारी सोच में जागरूकता, ज्ञान और सहभागिता को भी स्थान दिया जा रहा है। किसान को केवल सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि जानकारी से संपन्न, जागरूक और विकास की प्रक्रिया में भागीदार नागरिक मानना एक सकारात्मक दृष्टिकोण है।

वीर भारत न्यास ने इस आयोजन के माध्यम से किसानों को एक मंच पर जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसी पहलें यदि निरंतर आगे बढ़ती हैं, तो किसानों को सरकारी योजनाओं, कृषि संबंधी जानकारियों और नई संभावनाओं से जोड़ने के लिए भी उपयोगी माध्यम बन सकती हैं।

स्थापना दिवस पर किसानों के नाम एक अलग संदेश

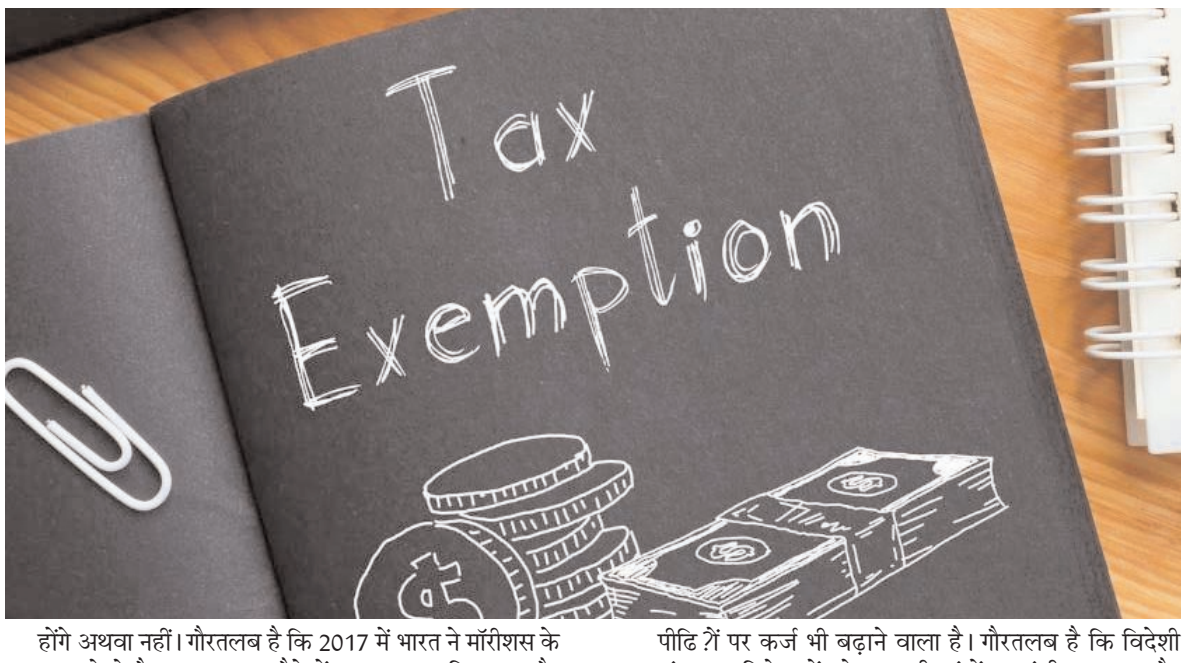
मध्यप्रदेश का 70वां स्थापना दिवस प्रदेश की सात दशक की विकास यात्रा को याद करने का अवसर है। इस यात्रा में किसान का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। खेतों में पसीना बहाने वाले अन्नदाताओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण जीवन को आधार दिया है। इसलिए स्थापना दिवस पर किसानों के सम्मान से जुड़ी यह पहल एक विशेष संदेश देती है कि प्रदेश का विकास तभी सार्थक है, जब उसके अन्नदाता और उनके परिवार भी इस विकास यात्रा में सम्मानित भागीदार बनें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाले वीर भारत न्यास ने किसानों के ज्ञान को प्रोत्साहन देकर सम्मान की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की है। ट्रैक्टर, बुलेट और ई-स्कूटी जैसे पुरस्कारों ने इसे आकर्षक बनाया, लेकिन इसकी असली उपलब्धि किसानों को यह अनुभव कराना है कि वे भी ऐसी प्रतियोगिताओं के केंद्र में हो सकते हैं, जिनकी कल्पना अब तक उनके जीवन से दूर मानी जाती थी। किसान के पसीने का सम्मान तो बहुत हुआ, अब उसके ज्ञान का सम्मान भी जरूरी है। मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर सामने आई यह पहल इसी विचार को आगे बढ़ाती है।

करों में छूट, नहीं है समाधान

डा. अश्विनी महाजन

निवेशकों द्वारा बिकवाली का तीसरा प्रमुख कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की बढ़ती कीमत और उसकी वजह से दुनिया के दूसरे भागों में वित्त की बढ़ती मांग है। चौथा कारण, रुपए का अवमूल्यन है। क्योंकि भारतीय रुपया पिछले समय में काफी ज्यादा गिर गया था, इसलिए निवेशकों को लाभ होने पर भी डॉलरों में वह लाभ बहुत हो जाता है। इसलिए वे बाहर की ओर रुख कर लेते हैं। पांचवां कारण यह है कि कई अन्य देशों में उभरते उद्योगों की वजह से वहां निवेश की संभावनाएं ज्यादा हैं। इस संदर्भ में दक्षिण कोरिया और ताईवान की ओर विदेशी निवेशक रुख कर रहे हैं। भारत में विदेशी निवेश पर लगने वाले कर अथवा केवाईसी के नियम अथवा अन्य भारतीय नियम विदेशी निवेशकों द्वारा बाहर का रुख करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।



पिछले काफी समय से भारत के शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में बिकवाली कर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर ले जा रहे हैं। वर्ष 2026-27 के प्रथम 7 महीने से भी कम समय में अभी तक विदेशी संस्थागत निवेशक 1.7 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं, जिससे रुपए पर दबाव बन रहा है और उसमें अवमूल्यन हो रहा था। नीति निमार्ता चिंतित हैं और तरह-तरह से प्रयास कर उन्हें भारत की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार पर उन्हें पहले से अधिक रियायतें देने संबंधी दबाव भी बन रहा है।

रियायतों का अंबार : यह तर्क दिया जा रहा था कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका करों में रियायत देने से संबंधित है। 5 जून 2026 को सरकार और रिजर्व बैंक ने स्वीकृत बांडों से होने वाले पूंजीगत लाभ को पूर्व के 12.5 प्रतिशत पूंजीगत लाभ कर और आयकर से छूट दी गई है। इसके अलावा पूर्व में जहां 15, 30 और 40 वर्ष के ब्रांड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब उन्हें इसकी अनुमति दी गई है। इसी प्रकार अन्य प्रकार की रियायतें भी विदेशी संस्थागत निवेशकों को दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद इन निवेशकों की बिकवाली बदस्तूर जारी है। लेकिन यह जरूर हुआ है कि अब विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सरकारी बांडों में निवेश बढ़ा दिया है। अब क्या मांग है विदेशी संस्थागत निवेशकों की? हालांकि सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों की सरकारी ऋण प्रतिभूतियों पर आयकर और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों से छूट पहले ही दे दी है, अब उनकी मांग है कि उन्हें शेयरों पर मिलने वाले पूंजीगत लाभों और अन्य लाभों पर कर से छूट मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि यह छूट उनको पहले भी प्राप्त थी। दूसरे, विदेशी निवेशक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में भी कमी चाहते हैं। गौरतलब है कि इस साल बजट में सरकार ने ह्यफ्यूचर और ऑप्शनह्ल (एफएंडओ) में एसटीटी को बढ़ाया था। पिछले सालों में एफएंडओ की वजह से रिटेल इन्वेस्टरों को बड़ा घाटा उठाना पड़ा था और इसका फायदा बड़ी विदेशी कंपनियों ने उठाया। सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) की रिपोर्ट के अनुसार 4850 करोड़ रुपए का गैर-कानूनी लाभ ह्यजेनस्ट्रीटह्ल सरीखी कंपनी ने एफएंडओ से कमाया। कुल मिलाकर कंपनी ने जनवरी 2023 और मार्च 2025 के बीच 36700 करोड़ रुपए का लाभ कंपनी ने कमाया। यह लाभ वास्तव में छोटे निवेशकों का नुकसान है। तीसरे, विदेशी संस्थागत निवेशक चाहते हैं कि प्राइवेट एक्टिविटी फंड टाइगर ग्लोबल, से संबद्ध मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसके बारे में यह स्पष्ट करें कि 2027 के पूर्व के निवेश पर भारतीय टैक्स लागू होंगे अथवा नहीं। गौरतलब है कि 2017 में भारत ने मॉरीशस के साथ दोहरे टैक्स वचन समझौते में बदलाव कर दिया था और मॉरीशस के रास्ते आने वाले निवेश पर कर लगाने का निर्णय लिया था। चौथे, विदेशी संस्थागत निदेशक अन्य प्रकार से सुविधाएं चाहते हैं, जैसे टैक्स रिफंड को आसान बनाना, केवाईसी और लाभार्थी का खुलासा करने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। समझा जा सकता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक वे सभी सुविधाएं चाहते हैं जो अभी तक घरेलू निवेशकों को उपलब्ध नहीं हैं। करों में छूट अथवा मुक्ति अथवा केवाईसी नियमों में छूट आदि देश के लिए अमंगलकारी होते हैं।

सर्वप्रथम, हालांकि सरकार ने पहले से ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से आय और पूंजीगत लाभों को कर मुक्त कर दिया है, यदि शेयरों को भी करों से मुक्त किया जाएगा तो उसका नुकसान सरकारी राजस्व को होगा, जिससे भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, जो महंगाई बढ़ाने वाला और भविष्य की पीढ़ि ों पर कर्ज भी बढ़ाने वाला है। गौरतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी बांडों पर पूंजीगत लाभ और आयकर में छूट से लगभग 10000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। अब जब विदेशी निवेशक यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें शेयरों पर होने वाले पूंजीगत लाभ और आय पर भी कर की छूट मिले, तो यह नुकसान कई गुना होने की संभावना है। दूसरे, विदेशी निवेशकों पर कर में रियायत को भारतीय निवेशकों के साथ भेदभाव भी माना जा सकता है। इससे भारतीयों द्वारा बचत का प्रोत्साहन घटेगा, जिससे विदेशियों पर निर्भरता बढ़ सकती है। तीसरे, विदेशी निवेशकों की एसटीटी कम करने की मांग, आय निवेशक के लिए अत्यंत घातक है। 2026-27 के बजट में एसटीटी बढ़ाने के कारण एफएंडओ में छोटे निवेशकों का आकर्षण कम हुआ है, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों का अनुचित लाभ कम हुआ है। ऐसे में एसटीटी को कम करने की मांग अनुचित तो है ही, यदि यह मांग मान ली जाएगी तो छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान जारी रहेगा। चौथे, विदेशी संस्थागत निवेशक चाहते हैं कि उनके लाभार्थी निवेशकों की जानकारी को गुप्त रखा जाए, इसलिए वे केवाईसी नियमों से छूट जाते हैं। इससे पहले यूपीए शासनकाल में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से भारत के शेयर बाजारों में पैसा लगाया जाता था। इस पद्धति का खासा विरोध हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से आतंकवादी संगठनों एवं अन्य प्रकार की गैर कानूनी स्त्रोतों से पैसा भारत के शेयर बाजार में आता है और उससे होने वाले लाभ भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि केवाईसी नियमों को शिथिल किया जाएगा तो यह कानूनी रूप से अनुचित ही नहीं, बल्कि गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे वाला होगा।

आर्थिक विश्लेषकों की क्या है राय : अधिकांश आर्थिक विश्लेषक यह मानते हैं कि करों में छूट अथवा अन्य सुविधाएं वास्तव में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली को नहीं रोक पाएगी क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक देश में करों अथवा नियमों के कारण बिकवाली नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया में बदलते हालात विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में उनके द्वारा शेयरों की बिक्री का कारण बन रहे हैं। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, और भारत से इन संस्थागत निवेशकों को खासा लाभ भी हुआ है। दशकों तक विदेशी संस्थागत निवेशक भारत से 30 से 40 प्रतिशत लाभ कमाते रहे हैं। वास्तव में विदेशी संस्थागत निवेशक कई अन्य कारणों से अपने शेयर बेच रहे हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण अमरीका में ब्याज दरों में वृद्धि और अमरीकी सरकार के बांडों पर आकर्षक लाभ है। पूर्व में अमरीका में फेडरल दर 0.25 प्रतिशत तक थी। लेकिन हाल ही के वर्षों में फेडरल रिजर्व (अमरीकी केंद्रीय बैंक) ने बढ़ती महंगाई के चलते फेडरल दर बढ़ा दी है, और वर्तमान में यह 3.75 से 4.0 प्रतिशत है। ऐसे में संस्थागत निवेशक वापसी का रुख कर रहे हैं। दूसरा प्रमुख कारण भू-राजनीतिक अनिश्चितता है। ऐसी किसी भी स्थिति में विदेशी निवेशक अपने घरेलू बाजारों की ओर रुख कर लेते हैं। इस स्थिति को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ह्यरन फॉर सेफ हेवनह्ल कहा जाता है।

न्यूज ब्रीफ

टीवी दिखाने के बहाने 9 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास

ग्वालियर। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में 9 साल की छात्रा को पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने 20 रुपए देकर दुकान से सामान लाने भेजा। उसके लौटने पर आरोपी ने टीवी दिखाने के बहाने अपने घर बुलाया और दरवाजा बंद कर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह वहां से निकलकर बच्ची घर पहुंची और पिता को घटना की जानकारी दी। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में सोमवार रात मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता चौथी कक्षा की छात्रा है। उसके माता-पिता निजी नौकरी करते हैं। सोमवार सुबह करीब 8 बजे दोनों काम पर चले गए थे। घर में बच्ची अपने छोटे भाई के साथ थी। दोपहर करीब 12:30 बजे पड़ोसी ने बच्ची का भरोसा जीतने के लिए उसे 20 रुपए दिए और दुकान से सामान लाने भेज दिया।

मध्य प्रदेश सरकार से निजी बसों के किराए में भारी वृद्धि रोकने की मांग

ग्वालियर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने त्यौहार के अवसर पर निजी बसों के किराए में भारी वृद्धि रोकने हेतु कड़ी कार्रवाई करने और निर्धारित दरों पर ही बसों का किराया लेना सुनिश्चित करने की मांग मध्य प्रदेश सरकार से की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड कौशल शर्मा एडवोकेट ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि दीपावली के त्यौहार के अवसर पर निजी बसों के किराए में चार गुना तक वृद्धि हो गई है। निजी बस मालिकों द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा है। गरीबी और महंगाई से जूझ रही जनता पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। सरकार का इस मनमाने बस किराए में वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस लूट से जनता त्रस्त है। निजी बसों के मालिकों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए किराए में वृद्धि पर नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा सरकार के संरक्षण में इस तरह जनता को लूटने की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कड़ी भर्त्सना की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार और विशेषकर परिवहन विभाग से यह मांग की है कि निजी बसों में मनमाने किराए में वृद्धि पर रोक लगाने हेतु कड़ी कार्रवाई की जाए और निर्धारित बस किराया लेना ही सुनिश्चित किया जाए ।

सड़क, वेतन आदि व्यवस्था के लिए महापौर ने लिखा निगमायुक्त को पत्र

ग्वालियर । महापौर डॉ शोभा सतीष सिंह सिकरवार ने आगामी दीपोत्सव पर्व को दृष्टिगत रखते हुये प्रकाश, सड़क, वेतन आदि व्यवस्था किये जाने के संबंध में निगमायुक्त को पत्र लिखकर अवगत कराया है। महापौर डॉ शोभा सतीष सिंह सिकरवार द्वारा लिखे गए पत्र के माध्यम से दीपोत्सव से पूर्व समस्त संबंधित कर्मचारियों को रात्रि भ्रमण कार्यक्रम के तहत बंद स्ट्रीट लाइट को चालू कराना सुनिश्चित किया जाये। मुख्य मार्गों को मोटरेबल किया जाये तथा जहाँ-जहाँ पेच रिपेयरिंग निगम अथवा गारंटी पीरियड में ठेकेदार से कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, उसके लिए डबल शिफ्ट में कार्य कराया जाये। समस्त फायर स्टाफ को चुस्त तथा त्वरित फायर कॉल के निराकरण हेतु 24म7 व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। त्यौहार पूर्व प्रतिदिन वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान संचालित कर शहर के गली मोहल्ले में सफाई कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

अमानक पॉलीथिन, गोबर नालियों में बहाने पर वसूला जुर्माना

ग्वालियर । शहर स्वच्छ व साफ रहे इसलिए गंदगी फैलाने वालों, अमानक पॉलीथिन, गोबर नालियों में बहाने वालों एवं भवन निर्माण सामग्री सडक पर डालने वालों पर निगम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम आयुक्त श्री अभिषेक चौधरी एवं अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। जिसके तहत स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म पमनानी के निर्देषन सैनिक कॉलोनी में भैंस डेयरी संचालकों द्वारा गोबर नाली में बहाने एवं खुले में फेंकने पर 6000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 26 के अंतर्गत गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों से 7750 रूपये का जुर्माना वसूला गया।

अपर आयुक्त टी प्रतीक राव ने किया साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण

लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर ।



नगर निगम के अपर आयुक्त टी प्रतीक राव ने शहर में साफ-सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य में लापरवाही, गंदगी और व्यवस्थाओं में कमियां पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र चौहान, सहायक यंत्री रामबाबू दिनकर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अपर आयुक्त टी प्रतीक राव ने सचिन तेंदुलकर रोड पर चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। कार्य की प्रगति संतोषजनक न मिलने और निर्धारित मानकों में कमी पाए जाने पर उन्होंने संबंधित इंजीनियर को नोटिस जारी करने तथा ठेकेदार को वार्निंग लेटर देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान हुरावली से बारादरी रोड पर भारी मात्रा में गंदगी फैली मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित जेडएचओ एवं डब्ल्यूएचओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। गौशाला और वहां संचालित सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया तथा पाया गया कि प्लांट पिछले 3 दिनों से बंद था। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्लांट प्रभारी और ठेकेदार को वार्निंग लेटर जारी करने और कल से ही हर हाल में काम सुचारू रूप से शुरू करने के निर्देश दिए गए।

गौशाला परिसर में अन्य कमियां मिलने पर प्रभारी को भी चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपर आयुक्त ने बेहटा रोड का भी निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अपर आयुक्त श्री राव ने निरीक्षण के दौरान पिंटू पार्क की मुख्य रोड पर अत्यधिक गंदगी मिलने पर डब्ल्यूएचओ एवं सहायक डब्ल्यूएचओ का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। साथ ही, वार्ड 20 के डब्ल्यूएचओ को उनके पद से हटाकर मूल पद पर भेजने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही वार्ड 20 की अंदरूनी कॉलोनियों में भारी संख्या में पशुओं के घूमने और गोबर, सीएंडडी कचरा मिलने पर तत्काल चलानी कार्रवाई करने तथा पशुओं की जब्ती की कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए गए।

आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं के उपचार एवं रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देश

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर ।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार सभी जिला कलेक्टर्स शासकीय जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित बर्न वार्ड एवं बर्न यूनिट का निरीक्षण करने एवं उन्हें उपचार के लिए पूर्णतः क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए हैं। बर्न वार्ड में आवश्यक बेड, दवाएं, चिकित्सा सामग्री, उपकरण एवं मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रतिदिन भर्ती बर्न इंजरी के मरीजों की स्थिति की समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पटाखों एवं आतिशबाजी से होने वाली बर्न इंजरी तथा अन्य दुर्घटनाओं के प्रभावी उपचार एवं रोकथाम के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को विशेष तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। सभी चिकित्सालयों में 24 घंटे चिकित्सकों, नर्सिंग ऑफिसर्स एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बर्न इंजरी, आंखों की चोट, हाथ-पैर की चोट, कानों को नुकसान तथा पटाखों के धुएं से होने वाली श्वसन संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं, चिकित्सा सामग्री एवं जांच उपकरण उपलब्ध रखे जाएं। सामान्य मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जाए तथा गंभीर मरीजों के लिए उनकी स्थिति के अनुरूप उपचार की कार्ययोजना तैयार की जाए। अवैध रूप से निर्मित कार्बाइड गन के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके विस्फोट से प्लास्टिक एवं धातु के छोटे कण आंख, चेहरे और त्वचा को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। एसीटिलीन गैस से जलने की घटनाएं भी हो सकती हैं। विशेषकर बच्चों एवं किशोरों में पलक, कंजंक्टाइवा एवं कॉर्निया को क्षति तथा स्थायी दृष्टिहानि का खतरा रहता है।

आनंद विभाग द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों तक दीपोत्सव की रोशनी पहुँचाने की पहल

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर ।



दीपावली आनंद और समृद्धि का पर्व है, लेकिन समाज में अनेक परिवार ऐसे हैं जिनके पास यह पर्व मनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे परिवारों के जीवन में भी उत्सव की रोशनी पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य आनंद संस्थान (आनंद विभाग) द्वारा हर घर दीपावली आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर जिले में भी आनंद विभाग द्वारा दीपोत्सव पर यह आयोजन किया जाएगा। आनंद विभाग अपने कार्यक्रमों में सहयोग की भावना को निरंतर प्रोत्साहित करता है। इसी भावना के तहत नागरिकों से आह्वान किया गया है कि वे अपने घरों या अन्य स्रोतों से अपनी आवश्यकता से अधिक तथा उपयोग में न आ रही वस्तुएँ संसाधनविहीन वर्ग तक पहुँचाएँ, ताकि दीपावली का पर्व हर घर में उल्लास के साथ मनाया जा सके। इस पहल को सफल बनाने के लिए सामाजिक संगठनों, एनजीओ, समाजसेवियों, आनंद क्लबों और आनंदक स्वयंसेवकों से आपसी समन्वय के साथ आगे आने की अपील की गई है। *जॉय ऑफ गिविंग* की इस मुहिम में आनंद विभाग के जिला संपर्क व्यक्ति, मास्टर ट्रेनर, आनंदम सहयोगी एवं आनंदक आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। आनंद विभाग का कहना है कि देने का सुख ही सच्चा आनंद है। जब एक घर का अतिरिक्त सामान किसी दूसरे घर की खुशी बनता है, तब दीपावली का वास्तविक अर्थ साकार होता है। आइए, इस दीपावली हम सब मिलकर किसी के जीवन में उजाला भरें और समृद्धि के इस पर्व को सही मायनों में सबका पर्व बनाएँ।

हत्या सहित डकैती के प्रकरण में ढाई साल से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को किया गिरफ्तार

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर ।



ग्वालियर जिले में फरार आरोपियों तथा स्थाई वारंटियों की धरपकड हेतु अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में आज थाना गिजोर्रा पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना गिजोर्रा के अप0क्र0-63/19 धारा 302,394,396 भादवि, 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट एवं माननीय न्यायालय डबरा के प्र.क्र. 14/19 में फरार स्थाई वारंटी वाहिद खान ग्राम जंगलपुरा के हार में बने वोर के पास जिला भिंड में देखा गया है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से प्रभारी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री जयराज कुबेर,(रापुसे) द्वारा थाना गिजोर्रा पुलिस को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया। थाना प्रभारी गिजोर्रा उनि0 उपेन्द्र सिंह धाकड़ के द्वारा थाना बल की टीम को मुखबिर के बताये स्थान पर भेजा गया। पुलिस टीम ने मौके पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति ग्राम जंगलपुरा के हार में बने वोर के पास खटिया पर लेटा हुआ मिला, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम वाहिद पुत्र जमील खान उम्र 45 साल निवासी ग्राम जंगलपुरा थाना मौ जिला भिण्ड बताया। उक्त आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय डबरा द्वारा प्र.क्र. 14/19 में स्थाई वारंट जारी होने से आरोपी को पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी के खिलाफ थाना गिजोर्रा में अप0क्र0-63/19 धारा 302,394,396 भादवि, 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट का अपराध पंजीबद्ध था, जिसमें आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष ट्रायल के दौरान फरार हो गया था। उक्त प्रकरण में शेष आरोपीगणों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। पकड़ा गया आरोपी ढाई साल से फरार चल रहा था, जिसकी तलाष पुलिस द्वारा निरंतर की जा रही थी, जिसे आज गिजोर्रा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

जैन मिलन युगल शाखा के द्वारा दीपावली पर जरूरतमंदो को सामान वितरण किया

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर ।



जैन समाज में अग्रणी संस्था जैन मिलन युगल नेमिनाथ ग्रेटर ग्वालियर शाखा द्वारा आज मंगलवार को सर्वोदय अहिंसा अभियान के अंतर्गत 'आओ मनाएं खुशियों भरी दिवाली' अभियान जरूरंतमद परिवारों को सामान वितरण कर कार्यकम आयोजित किया गया। ऐसे परिवारों के जीवन में खुशियों की रोशनी पहुंचाने के उद्देश्य से दीपावली खुशियों, उमंग और रोशनी का पर्व है। इस अवसर पर हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने की तैयारी करता है, लेकिन समाज में अनेक ऐसे निर्धन एवं जरूरतमंद परिवार भी हैं, जिनके लिए त्योहार की आवश्यक सामग्री जुटाना कठिन होता है। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जैन मिलन के शाखा संस्थापक एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रवि जैन, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी सचिन जैन, क्षेत्रीय संयोजक पारस जैन एवं क्षेत्रीय ग्रीटिंग सह संयोजकठ्ठ ऋषभ जैन के द्वारा जैन ध्वज दिखाकर सर्वोदय अहिंसा रथ को रवाना करके किया। यह रथ जैन ध्वज के साथ शहर की विभिन्न जरूरतमंद बस्तियों तक पहुंचकर दीपावली किट का वितरण किया गया। इस सेवा अभियान के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को सामना दीनदयाल गेट एवं गोले का मंदिर, भिंड रोड स्थित झुग्गी-बस्ती सहित विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंद परिवारों को दीपावली किट वितरित की गई। इस किट में खिले फल, मिठाई, कपड़े, मिट्टी के दीपक, रूई, तेल, बिस्कुट एवं दीपावली के लिए अन्य आवश्यक सामग्री शामिल थी।

दान की वस्तुओं से रोशन होगी दिवाली 1 रुपए में मिलेगा जरूरत का सामान

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर ।



दीपावली के पर्व पर घरों से निकलने वाली अनुपयोगी वस्तुओं को कचरे में जाने से बचाने और उन्हें जरूरतमंद परिवारों के उपयोग में लाने के उद्देश्य से नगर निगम ग्वालियर द्वारा 'स्वच्छ दिवाली 01 रुपये वाली' विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 21 अक्टूबर से संचालित इस अनूठे अभियान में आम नागरिक बढ़-चढ़कर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने घर की अनुपयोगी सामग्री दूसरों के उपयोग के लिए प्रदान कर रहे हैं। शहर के नागरिकों ने 3 नवम्बर 2026 तक 14 दिनों में अनुपयोगी समझी जाने वाली 25067 वस्तुओं को नगर निगम की गाड़ियों एवं कार्यालय में जमा कराया। उक्त सामग्री वितरण का शुभारंभ 5 नवम्बर 2026 को सुबह 10:30 बजे से बाल भवन में होगा। इसके साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से उक्त सामग्री का वितरण किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक चौधरी के निर्देशन में संचालित इस अभियान के संबंध में अपर आयुक्त श्री टी. प्रतीक राव ने बताया कि दीपावली के दौरान घरों की साफ-सफाई में बड़ी संख्या में ऐसी वस्तुएं बाहर निकलती हैं, जिनका उपयोग थोड़ी मरम्मत या उचित रखरखाव के बाद दोबारा किया जा सकता है। अक्सर ये वस्तुएं कचरे में पहुंच जाती हैं, जिससे अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत शहर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विशेष संग्रहण वाहन संचालित किए जाएंगे, जो घरों से पुनः उपयोग योग्य सामग्री एकत्रित करेंगे। नागरिक अपने नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय में भी ऐसी वस्तुएं जमा करा सकते हैं।

जिले के ग्राम कुलैथ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा पशु पालक सम्मेलन

जिला पंचायत सीईओ ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में की तैयारियों की समीक्षा

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर ।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में जिले के ग्राम कुलैथ में 13 नवंबर को पशु पालक सम्मेलन प्रस्तावित है। मंगलवार को हुई अंतरविभागीय समन्वय बैठक में इस सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर कृषि व कृषि अभियांत्रिकी, पशु पालन व डेयरी, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी सहित खेती से जुड़े अन्य विभाग प्रभावी व आकर्षक प्रदर्शनियां लगाएं, जिससे किसान एवं पशु पालक इन प्रदर्शनियों को देखकर विभागीय योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने पशु पालक सम्मेलन की सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। कुलैथ में आयोजित होने जा रहे इस सम्मेलन के दौरान बैलगाड़ी दौड़ सहित अन्य गतिविधियां भी प्रस्तावित हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा जिले के भ्रमण के दौरान की गई घोषणाओं का पालन कराने के निर्देश भी दिए गए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रावत ने निर्देश दिए कि इस काम को गंभीरता से लें और घोषणाओं को धरातल पर लाएं। इसमें कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर , पराली व नरवाई प्रबंधन, स्वामित्व अधिकार के तहत रजिस्ट्री एवं चीता जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों की भी समीक्षा की गई। जिला पंचायत सीईओ ने दीपावली त्योहार को ध्यान में रखकर अस्पतालों में प्राथमिक बर्न यूनिट तैयार करने के निर्देश स्वास्थय विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में वन मंडल अधिकारी मुकेश पटेल, अपर कलेक्टर सी.बी प्रसाद व अनिल बनवारिया, जिले के एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को गंभीरता से लें। अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में समस्याओं के निराकरण के साथ -साथ सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर अपने-अपने विभाग से संबंधित संस्थाओं का निरीक्षण करें। साथ ही हितग्राहियों से संपर्क कर योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लें। उन्होनें विभागीय अधिकारियों से निरीक्षण की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद पंचायतों के सीईओ और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से जन विश्वास शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण का ब्यौरा आवेदकों के नाम सहित शिविरवार मांगा है। जिले में पराली एवं नरवाई प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। उन गांवों में चौपाल लगाकर व कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया गया है।



मेरी डिक्शनरी में डर शब्द नहीं: गंभीर

कप्तान अय्यर ने कहा- गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार की जरूरत

नई दिल्ली। भारत ने न्यूजीलैंड को 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 3-2 से हराया। सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, मेरी डिक्शनरी और डायरेक्टरी में डर नाम का कोई शब्द नहीं है। गंभीर ने पहले मैच का उदाहरण देते हुए खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि टीम ने 15 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद सिर्फ एक अभ्यास सत्र किया था, इसके बावजूद मुकाबला जीत लिया। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि गेंदबाजी और फील्डिंग बेहतर हो सकती थी। वहीं न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को सीरीज का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने पांच मैचों में 341 रन बनाए।

- **ध्यान अब वनडे सीरीज पर: अय्यर** - अय्यर के मुताबिक, न्यूजीलैंड में खेलने के दौरान खिलाड़ियों को अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आसमान में साफ रोशनी और मैदान पर अंधेरे जैसी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियां भारत में आमतौर पर देखने को नहीं मिलतीं। कप्तान ने यह भी कहा कि टीम इन कमियों पर चर्चा करेगी। हालांकि, उनका ध्यान अब वनडे सीरीज पर है और खिलाड़ी अच्छे मूड में हैं।
- **ऋषभ पंत की चोट पर गंभीर के पास अपडेट नहीं** - प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर से ऋषभ पंत की उपलब्धता को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास पंत की चोट को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं है।

थकान के बावजूद जीत हासिल की

गंभीर ने कहा, विदेशी परिस्थितियों में खेलते समय टीम को मुश्किल हालात से घबराना नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को लंबी यात्रा और कम अभ्यास का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पहले मैच में जीत हासिल करना आसान नहीं था। गंभीर ने इसी प्रदर्शन को टीम की मानसिक मजबूती का उदाहरण बताया। सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों में भारत ने लगातार जीत दर्ज की। इसके बाद न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए आखिरी दोनों मैच अपने नाम किए।

सीरीज का नतीजा उलटा भी हो सकता था- सैंटनर

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने माना कि सीरीज काफी करीबी रही। उनके मुताबिक, शुरुआती दो मुकाबलों में कुछ ऐसे मौके आए, जिन्हें न्यूजीलैंड भुना सकता था। अगर टीम उन मौकों पर बेहतर प्रदर्शन करती, तो सीरीज का नतीजा भारत के बजाय न्यूजीलैंड के पक्ष में भी हो सकता था। सैंटनर ने गेंदबाजी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आखिरी दो मैचों में गेंदबाजों ने परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदली। तेज गेंदबाजों ने यॉर्कर, वाइड गेंदों और सही लेंथ का इस्तेमाल किया।

पीवी सिंधु ने रचा इतिहास

हाइलो ओपन जीतकर सीजन का दूसरा खिताब अपने नाम किया

जर्मनी: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने एक बार फिर अपने शानदार खेल से देश का नाम रोशन किया है। सिंधु ने जर्मनी में खेले गए हाइलो ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में डेनमार्क की लाइन केजर्सफेल्ट को सीधे गेमों में 21-12, 21-14 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सिंधु ने मौजूदा सीजन का अपना दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है।

पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहीं सिंधु - सिंधु का हाइलो ओपन में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। उन्होंने फाइनल तक के सफर में एक भी गेम नहीं गंवाया। अपने अभियान की शुरुआत उन्होंने भारतीय खिलाड़ी प्रकृति भरत को हराकर की। इसके बाद फ्रांस की रोजी ओक्टाविया पंकासारी और जर्मनी की अमाली शुल्ज को मात देकर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उन्होंने भारत की ही अनमोल खरब को 21-13, 21-16 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया।

39 मिनट में फाइनल जीतकर बनीं चैंपियन

पीवी सिंधु ने फाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पहला गेम महज 17 मिनट में 21-12 से जीतकर डेनमार्क की खिलाड़ी पर दबाव बना दिया। इसके बाद दूसरे गेम में भी सिंधु ने अपनी लय बरकरार रखी और 21-14 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय शटलर ने यह फाइनल केवल 39 मिनट में जीतकर शानदार अंदाज में खिताब पर कब्जा किया।

जापान ओपन के बाद अब हाइलो ओपन पर कब्जा

पीवी सिंधु के लिए यह साल खिताब के लिहाज से शानदार रहा है। उन्होंने जुलाई में जापान ओपन 2026 के फाइनल में जापान की तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को हराकर खिताब जीता था। अब हाइलो ओपन जीतकर उन्होंने इस सीजन का दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम कर लिया है।



फ्रैंकफर्ट ने हैम्बर्गर को 3-1 से हराया, टॉप-8 में हुई एंट्री



बर्लिन। आइनट्राख्त फ्रैंकफर्ट ने हैम्बर्गर एसवी को 3-1 से हराकर बुंडेसलिगा लीग में आठवां स्थान हासिल कर लिया है। जर्मन कप में जीत के बाद पांच दिनों के भीतर हैम्बर्ग के खिलाफ यह उनकी दूसरी जीत है। 59 हजार दर्शकों के सामने फ्रैंकफर्ट ने शानदार शुरुआत की और 10वें मिनट में ही बढ़त बना ली। कैन उजुन ने पेनल्टी एरिया में फेरेस चैबी को गेंद पास की, जिसे हैम्बर्ग के डिफेंडर वार्मड ओमारी ने रोकने की कोशिश में अपनी ही गोल पोस्ट में डाल दिया। चार मिनट बाद हैम्बर्ग ने बराबरी कर ली। लिलियन ब्रासियर, मिरो मुहेम की गेंद को ठीक से नहीं संभाल पाए, जिसका फायदा उठाते हुए अल्बर्ट ग्रोनबेक ने टेरेम मोफी को पास दिया। मोफी ने करीब से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम से ठीक पहले फ्रैंकफर्ट के कप्तान रॉबिन कोच ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर डैनियल ह्यूअर फर्नांडीस ने उनके हेडर को बाहर धकेल दिया। हाफ टाइम के तुरंत बाद फ्रैंकफर्ट ने फिर से बढ़त बना ली। चैबी के कॉर्नर पर ब्रासियर ने हेडर लगाया, जिसे ह्यूअर फर्नांडीस पूरी तरह रोक नहीं पाए। रिबाउंड पर राफेल ओन्येदिका ने 47वें मिनट में गोल किया।

सेंथिलकुमार ने चेक ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में बनाई जगह



ब्रनो। भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने ब्रनो में चल रहे चेक ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। 35,000 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस पीएसए कॉपर-लेवल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी और विश्व नंबर 32 ऑगस्ट डुसॉर्ड को हराया। सेंथिलकुमार ने सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी को 11-7, 12-10, 11-1 से मात दी। चौथे वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी अब फाइनल में स्कॉटलैंड के ग्रेग लोबन (जो शीर्ष वरीयता प्राप्त हैं और विश्व रैंकिंग में 31वें नंबर पर हैं) का सामना करेंगे। सेंथिलकुमार इस सीजन में अपना दूसरा खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त लोबन ने फ्रांस के तौफिक मेखल्फी को 11-9, 11-5, 11-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले, सेंथिलकुमार ने अर्जेंटीना के जेरेमियास अजाना को 11-3, 11-8, 11-7 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। पहले गेम में भारतीय खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के जेरेमियास अजाना को आसानी से 11-3 से हराया।



दिल्ली में नहीं खेल पाएंगे विराट कोहली

श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे की मेजबानी पर संकट

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली को अपने घरेलू मैदान दिल्ली में खेलते हुए देखने का इंतजार कर रहे फैंस को निराशा हाथ लग सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के पहले मुकाबले की मेजबानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम से छिन सकती है। हालांकि, बीसीसीआई की ओर से वेन्यू बदलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

विराट कोहली की दिल्ली वापसी का इंतजार कर रहे थे फैंस - विराट कोहली के लिए दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम बेहद खास है। इसी मैदान और दिल्ली के घरेलू क्रिकेट से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2019 में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए स्टेडियम के एक प्रमुख स्टैंड का नाम 'विराट कोहली पवेलियन' रखा था। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली में होने वाला वनडे मुकाबला स्थानीय फैंस के लिए कोहली को अपने घरेलू मैदान पर देखने का शानदार अवसर हो सकता था।

- **आउटफील्ड के निर्माण कार्य के कारण बदला जा सकता है वेन्यू** - दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस समय आउटफील्ड को आधुनिक बनाने का काम चल रहा है। डीडीसीए ने मैदान में सैंड बेस्ड ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने का फैसला किया है। इस तकनीक से बारिश के बाद मैदान से पानी तेजी से निकल सकेगा और मैच दोबारा शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे काम को पूरा होने में करीब चार महीने लगेंगे और स्टेडियम आईपीएल 2027 से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा।

अरुण जेटली स्टेडियम में आखिरी वनडे कब खेला गया था?

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला 11 अक्टूबर 2023 को खेला गया था। यह आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला था, जिसमें भारत ने अफगानिस्तान को आठ विकेट से हराया था। फिलहाल स्टेडियम में निर्माण कार्य के चलते दिल्ली की घरेलू टीम को भी अपने रणजी ट्रॉफी मुकाबले पालम स्थित एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में खेलने पड़ रहे हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी में जुटे विराट कोहली

दूसरी ओर विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। टी20 सीरीज खत्म होने के बाद वह न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं और नेट्स में अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद कोहली का फोकस अब मुख्य रूप से वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर है।

एंटोनेली ने सबसे कम उम्र के एफ1 चैंपियन का खिताब जीता

नई दिल्ली। किमी एंटोनेली ने रविवार को इतिहास रचते हुए फॉर्मूला वन के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 20 वर्षीय मर्सिडीज ड्राइवर ने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टापेन और लुईस हैमिल्टन के बाद तीसरे स्थान पर रहकर यह उपलब्धि प्राप्त की।

किमी, जो फॉर्मूला वन रेसिंग में अपने दूसरे ही सीजन में हैं, ने सेबेस्टियन वेटेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2010 में अपनी चार ड्राइवर चैंपियनशिप में से पहली चैंपियनशिप जीतने के समय 23 साल और 133 दिन के थे। अपनी उपलब्धि की वास्तविकता को समझते हुए किमी अपने आँसू रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

टीम रेडियो पर, नव-ताजपोश विश्व चैंपियन पहले तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मर्सिडीज को अपने सपने को साकार करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। 'हमने कर दिखाया! हमने कर दिखाया!' उसे हंसते-हंसते आंसुओं के साथ कहते हुए सुना गया। इसके बाद जो जश्न मनाया गया, वह इस अवसर के अनुरूप ही था।

पोडियम पर एंटोनेली अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे, तभी वर्स्टापेन और हैमिल्टन ने भी उनका साथ दिया और नव-प्रतिभाशाली चैंपियन को हवा में उठा लिया। यह एक यादगार दृश्य था: खेल के दो महानतम ड्राइवर फॉर्मूला वन चैंपियन की नई पीढ़ी के आगमन का जश्न मना रहे थे। मैं भविष्य में और अधिक मुकाबलों के लिए उत्सुक हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'यह तो बस शुरुआत है।' एंटोनेली के लिए, यह सात साल के कार्टिंग के शौकीन से लेकर मोटरस्पोर्ट के शिखर तक की एक उल्लेखनीय यात्रा की परिणति थी।



मर्सिडीज टीम के प्रमुख टोटो वोल्फ के लिए भी, 2025 सीज़न से पहले हैमिल्टन की जगह 18 वर्षीय खिलाड़ी को मौका देने के उनके महत्वपूर्ण जोखिम भरे फैसले की पुष्टि का क्षण था।

उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक मोंज़ा में देखने को मिला, जहाँ उन्होंने ग्रिड पर 19वें स्थान से शुरुआत करने के बावजूद अपने घरेलू ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की।

एक यादगार दूसरा सीज़न

एंटोनेली के चैम्पियनशिप जीतने वाले अभियान की विशेषता उनकी गति, निरंतरता और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रही है। सीज़न के तीसरे दौर, जापानी ग्रांड प्रिक्स के बाद उन्होंने ड्राइवर्स चैंपियनशिप में बढ़त हासिल कर ली और अपने प्रतिद्वंद्वियों पर निर्णायक बढ़त बना ली। उन्होंने शुरुआती छह रेसों में से पांच में जीत हासिल की और सीज़न आगे बढ़ने के साथ-साथ अपनी इस लय को बरकरार रखा। जब चैंपियनशिप मैक्सिको पहुंची, तब तक एंटोनेली नौ ग्रांड प्रिक्स जीत चुके थे। उन्होंने केवल दो रेसों में अंक हासिल नहीं किए, और दोनों बार यांत्रिक समस्याओं के कारण ऐसा हुआ।

मेसी का शानदार प्रदर्शन, इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन को 2-1 से हराया

फॉक्सबोरो। लियोनेल मेसी ने एक बेहतरीन असिस्ट और मैच के आखिर में किए गए गोल की मदद से इंटर मियामी को न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन के खिलाफ 2-1 से जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही टीम ने अगले साल होने वाले कॉन्काकैफ चैंपियंस कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत से मियामी एमएलएस कप प्लेऑफ से पहले ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में नंबर 2 सीड की स्थिति में पहुंच गई है। इस सीजन में मेसी के नाम अब 26 गोल और 16 असिस्ट हो गए हैं। इसके साथ ही वह लगातार तीसरी बार एमएलएस एमवीपी अवार्ड और लगातार दूसरी बार 'गोल्डन बूट' जीतने की रेस में सबसे आगे हो गए हैं।

पहले 45 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला रहा और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस दौरान इंटर मियामी को 28वें मिनट में एक अच्छा मौका मिला, जब मेक्सिकन खिलाड़ी बर्टेरामे ने बॉक्स के बाई ओर से बाएं पैर से शॉट मारा, जिसे न्यू इंग्लैंड के गोलकीपर मैट टर्नर ने बचा लिया। दूसरे हाफ में, 53वें मिनट में डेनियल गाजदाग के गोल की बदौलत मेजबान टीम (न्यू इंग्लैंड) ने खाता खोला। 69वें मिनट में इंटर मियामी ने शानदार टीम वर्क दिखाते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। सेगोविया ने बॉक्स के अंदर एक 'लॉब' पास दिया, जिस पर मेसी ने हेडर से गेंद को बर्टेरामे की तरफ बढ़ाया। बर्टेरामे ने बॉक्स के बीच से एक जोरदार हेडर लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। यह इस रेगुलर सीजन में बर्टेरामे का 10वां गोल था, जबकि मेसी का यह इस लीग सीजन का 16वां असिस्ट रहा।



83वें मिनट में इंटर मियामी ने मैच का पासा पूरी तरह से पलटा। एक बेहतरीन पासिंग सीक्वेंस के बाद मेसी ने निर्णायक गोल किया। सुआरेज ने बॉक्स के बाहर बीच में मेसी को गेंद दी, जहां अर्जेंटीना के इस स्टार खिलाड़ी ने तीन डिफेंडरों को छकाया। इसके बाद सेगोविया के साथ मिलकर वह बॉक्स के अंदर पहुंचे और एक सटीक शॉट के जरिए गेंद को गोल पोस्ट के निचले दाएं कोने में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ मेसी के कुल गोल की संख्या 26 हो गई है, जिससे वह एमएलएस 2026 गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। वहीं, इस रेगुलर सीजन में सेगोविया के असिस्ट की संख्या 12 हो गई है। इसके बाद 1-2 की स्कोरलाइन अंतिम सीटी बजने तक कायम रहा, जिससे इंटर मियामी ने अपने घर से बाहर खेलते हुए तीन अंक हासिल किए।

निरीक्षण में अभिलेखों एवं स्टॉक संधारण में मिली गंभीर खामियां

बीज विक्रय में अनियमितताएं पाए जाने पर पोरसा के कालिका मां कृषि सेवा केन्द्र का लाइसेंस निलंबित

एक सत बुलेटिन, मुरैना



कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने तथा बीज विक्रय व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कृषि विभाग द्वारा बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में निरीक्षण के दौरान बीज विक्रय संबंधी अभिलेखों एवं स्टॉक संधारण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने तथा कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर पोरसा स्थित जय कालिका मां कृषि सेवा केन्द्र का बीज विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं बीज अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मैसर्स जय कालिका मां कृषि सेवा केन्द्र, प्रोपराइटर श्री रामवीर सिंह तोमर, अटेर रोड, पोरसा का 20 अक्टूबर 2026 को बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड पोरसा द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर बीज विक्रय संबंधी अभिलेखों एवं स्टॉक संधारण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं के संबंध में कृषि विभाग द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को फर्म को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण एवं संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समयावधि में फर्म द्वारा न तो संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और न ही विभाग द्वारा चाही गई जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराए गए। प्रकरण में प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण में बीज विक्रय तथा अभिलेखों के संधारण में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर इसे बीज गुण (नियंत्रण) आदेश, 1983 एवं बीज विक्रय अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन माना गया। इस आधार पर उक्त आदेश के खंड 15 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए फर्म का बीज विक्रय लाइसेंस को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। लाइसेंस निलंबित रहने की अवधि में संबंधित फर्म बीज विक्रय का कार्य नहीं कर सकेगी। साथ ही, फर्म को आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर आवश्यक अभिलेखों सहित कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए बीज लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के संबंध में तहसीलदार जौरा ने जारी की सार्वजनिक सूचना



एक सत बुलेटिन, मुरैना।

तहसीलदार तहसील जौरा द्वारा मौजा घुरैयावसई स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1171/2 पर निर्मित मकान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। उक्त शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा कार्रवाई के लिए दल गठित किया गया।

निर्धारित कार्रवाई के तहत गठित दल मौके पर पहुंचा, लेकिन शासकीय भूमि पर निर्मित मकान पर ताला लगा हुआ पाया गया। मकान के अंदर घरेलू सामान रखा हुआ था। इस संबंध में अनावेदक नथुआ पुत्र नवलसिंह एवं छोटे पुत्र नवलसिंह के रिश्तेदारों तथा परिचितों को सूचित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मकान में रखे सामान की सुपुर्दगी प्राप्त करना चाहता है, तो वह 12 नवम्बर 2026 तक तहसील कार्यालय जौरा में उपस्थित होकर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सामान प्राप्त कर सकता है। तहसीलदार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में संबंधित व्यक्ति के उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में होने वाली कार्रवाई की समस्त जिम्मेदारी संबंधित अनावेदक की स्वयं की होगी।

सभी पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एचपीआर आईडी बनवाना अनिवार्य



एक सत बुलेटिन, मुरैना

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सुदृढ़, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय मुरैना में कार्यरत सभी पात्र चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुरैना द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में कार्यरत समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा में एचपीआर आईडी बनवाना अनिवार्य होगा। पंजीयन के लिए संबंधित कर्मचारियों को आधार कार्ड, आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर, सक्रिय ई-मेल आईडी, नर्सिंग पंजीयन प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो), डिप्लोमा एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र तथा पंजीयन आदेश की प्रति उपलब्ध रखनी होगी। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एचपीआर आईडी पूर्व से बनी हुई है, उन्हें निर्धारित पोर्टल पर लॉगिन कर अपना हेल्थ प्रोफेशनल कार्ड डाउनलोड करना होगा। वहीं, जिनका पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण कर एचपीआर आईडी बनवाने के बाद हेल्थ प्रोफेशनल कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। सिविल सर्जन ने सभी विभागाध्यक्षों एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभाग के शत-प्रतिशत पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एचपीआर पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराएं। साथ ही पंजीयन कार्य की नियमित समीक्षा एवं निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र अधिकारी या कर्मचारी इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। निर्धारित समय-सीमा में एचपीआर आईडी नहीं बनवाने की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की स्वयं की होगी।स्वास्थ्य विभाग के सभी पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनवाना अनिवार्य किया गया है। विभाग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करें। निर्देशों के अनुसार, बनने के बाद संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को हेल्थ प्रोफेशनल कार्ड भी डाउनलोड करना होगा।

कलेक्टर ने स्वामित्व रजिस्ट्री में कम प्रगति पर पांच राजस्व अधिकारियों को दिया नोटिस

भिण्ड। कलेक्टर श्री पवन जैन ने स्वामित्व रजिस्ट्री में कम प्रगति पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार श्री प्रदीप मिश्रा, तहसीलदार भिण्ड श्री मोहनलाल शर्मा, तहसीलदार मिहोना श्री हरिओम पचौरी, नायब तहसीलदार वृत्त पीपरी श्री देवेन्द्र तोमर, नायब तहसीलदार वृत्त ऊमरी श्रीमती रूपम गुप्ता को कारण बताओ नोटिस दिया है। कलेक्टर श्री जैन ने सूचित किया है कि शासन की महत्वपूर्ण योजना स्वामित्व रजिस्ट्री में जिला स्तर से प्रगति बढाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है इसके विपरीत अनुभाग लहार में प्रगति कम होने से अनुभाग में कुल लक्ष्य (कुल प्लाट) 34530 के विरुद्ध मात्र 5634 (16.31 प्रतिशत), तहसील भिण्ड, वृत्त पीपरी, वृत्त ऊमरी में प्रगति कम होने से तहसील में कुल लक्ष्य (कुल प्लाट) 23028 के विरुद्ध मात्र 2915 (12.66 प्रतिशत), तहसील मिहोना में कुल लक्ष्य (कुल प्लाट) 7927 के विरुद्ध मात्र 1080 (13.62 प्रतिशत) रजिस्ट्रियां ही संपन्न हुई हैं जो कि जिला स्तर पर अत्यंत निम्न है जिससे प्रदेश स्तर पर जिले की छवि धूमिल हो रही है। उक्त कृत्य शासकीय कार्य में घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना का परिचायक होकर कदाचार की श्रेणी में आता है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 के अंतर्गत दंडनीय है।

आर्यावर्त विश्वविद्यालय और सिग्निफिक करियर्स के बीच अनुबंध, विद्यार्थियों को मिलेंगे रोजगार के अवसर

एक सत बुलेटिन, सीहोर।

आर्यावर्त विश्वविद्यालय, सीहोर ने विद्यार्थियों के कौशल विकास और उन्हें रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से भोपाल की सिग्निफिक करियर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2 नवंबर 2026 को अनुबंध किया। इस अनुबंध के तहत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। अनुबंध के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, करियर मार्गदर्शन, विशेषज्ञों के व्याख्यान और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव देना और रोजगार के लिए तैयार करना है। अनुबंध पर कंपनी की ओर से फाउंडर एन्ड सेल्स हेड श्री राघव बंगार्ड तथा आर्यावर्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव डॉ. अनुज सिंघई ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान कंपनी के सह-संस्थापक एवं अनुसंधान प्रमुख डॉ. सचिन रसल और एच. आर. मैनेजर आकाश रेशमी भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय की ओर से कुलगुरु प्रोफ. (डॉ.) दीपक राज तिवारी, प्रतिकुलगुरु डॉ. गिरीश त्रिपाठी, उपकुलसचिव डॉ. अनिवेद मिश्रा एवं प्रशिक्षण एवं नियुक्ति प्रकोष्ठ से डॉ. दीपक गर्ग उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति विभाग की इस पहल को विद्यार्थियों की रोजगारपरक क्षमताओं को विकसित करने और उन्हें उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



भिण्ड में 30 बसों की सुरक्षा जांच, इमरजेंसी गेट तत्काल खुलवाए, 7,500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई

एक सत बुलेटिन, भिण्ड



भिण्ड बस स्टैंड पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। परिवहन आयुक्त ग्वालियर, कलेक्टर भिण्ड श्री पवन जैन एवं पुलिस अधीक्षक श्री सूरज वर्मा के आदेश पर जिला परिवहन अधिकारी श्री राजेंद्र सोनी के निर्देशन में 30 बसों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान कई बसों के इमरजेंसी गेट नहीं खुल रहे थे। प्रशासन ने तत्काल संचालकों से गेट खुलवाकर उनकी कार्यक्षमता जांची। सभी बस संचालकों को सुरक्षा उपकरणों की कमी पूर्ति करने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। नियम भंग करने पर 7,500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान प्रभारी अधिकारी फूप श्री अशोक शर्मा, ट्रैफिक टीआई श्री इंद्रपाल सिंह एवं विभागीय स्टाफ मौजूद रहा। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है और सीएम मॉनिट में प्राप्त निर्देशों के पालन में इसी तरह की जांच नियमित रूप से जारी रहेगी।

पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद खेत में लगाई आग, कृषि विभाग के दल ने मौके पर पहुंचकर बनाया पंचनामा

भिण्ड। कलेक्टर भिण्ड श्री पवन जैन द्वारा जिले में पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने तथा कृषि विभाग द्वारा किसानों को निरंतर समझाइश देने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में आज विकासखण्ड गोहद के ग्राम चक खनेता एवं इकहरा में एक किसान द्वारा फसल अवशेष (पराली) में आग लगाई गई। सूचना प्राप्त होते ही कृषि विभाग का दल एवं संबंधित पटवारी तत्काल मौके पर पहुंचे। दल द्वारा मौके पर स्थिति का निरीक्षण किया गया तथा पराली जलाने से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में किसान को समझाइश दी गई। घटनास्थल का पंचनामा तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण संज्ञान में लिया गया। कृषि विभाग द्वारा किसानों को बताया गया कि पराली जलाने से मिट्टी में उपलब्ध जैविक पदार्थ एवं लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है तथा मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि होती है। इसके अतिरिक्त आग से आसपास की खड़ी फसलों, पेड़-पौधों एवं जनसंपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।



बालिकाओं को कलेक्टर द्वारा बांटी गई प्रशिक्षण सामग्री

ईमानदारी के साथ मेहनत का दिया संदेश, सशक्त वाहिनी योजना के तहत बेटियों को मिल रहा प्रशिक्षण

एक सत बुलेटिन, भिण्ड

कलेक्टर श्री पवन जैन के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री महेंद्र सिंह अंब के निर्देशन में तथा प्रशासनम् इंस्टीट्यूट भिण्ड के माध्यम से विगत डेढ़ माह से पुलिस कांस्टेबल एवं प्रतियोगी परीक्षा हेतु जिलेभर से चयनित आधा सैकड़ा से अधिक बालिकाओं का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत सशक्तवाहिनी निःशुल्क प्रशिक्षण चल रहा है। आज सशक्त वाहिनी कक्षाओं में अध्ययन प्रशिक्षण किट कलेक्टर श्री पवन जैन द्वारा वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर श्री पवन जैन ने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहीं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिण्ड की माटी वीर सपूतों की माटी है यहां साहस और दृढ़ता की कमी नहीं है भिण्ड की बेटियां भी अब सेना और पुलिस में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहीं है। आप सभी भी अच्छे से पढ़ाई करें और अपने जिले तथा माता पिता का नाम रोशन करें। याद रखें नियमित अध्ययन और अनुशासन से ही सफलता मिलती है इसका कोई शॉर्ट कट नहीं है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के पलों को भी साझा किया। कलेक्टर श्री जैन न बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कोई भी काम ऐसा नहीं है, जिसे हम कर नहीं सकते, हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाकर प्रयास करें। केवल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा ही लक्ष्य न हो अपितु वह एक प्राथमिक सफलता हो। आप चयन के बाद भी नए आयाम छुएं। शर्त बस यही है कि हमें निरंतर, नियमित संयमित और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। उपस्थित शिक्षकगणों से भी अपेक्षा की गई कि परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसार तैयारी कराई जावे। परीक्षा के पूर्व खूब मॉक टेस्ट कराए जावें ताकि जितनी भी गलतियां होनी हैं प्रैक्टिस में हो जाएं परीक्षा में नहीं। प्रशासन की अपेक्षा है कि आप अधिक से अधिक परीक्षा में उत्साहपूर्ण प्रतिभागिता करें और चयन निश्चित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभिनव पहल बालिकाओं को और महिलाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री महेंद्र सिंह अंब द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग का लक्ष्य है कि भिण्ड की अधिक से अधिक बेटियों का चयन शासकीय सेवाओं में हो। ताकि बेटियों को लेकर समाज में जो रूढ़िवादी सोच है उसको बदला जा सके। बालिकाओं को समस्त प्रशिक्षण सामग्री किताबें, कॉपी, नोट्स और मॉक टेस्ट, समस्त सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बालिकाओं का चयन होगा वह जिले का नाम रोशन करें। बाल सरंक्षण अधिकारी श्री अजय सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि सशक्त वाहिनी योजना का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के माध्यम से बालिका हितेशी वातावरण का निर्माण करना है और बालिकाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त और संबल बनाना है। हमारा प्रयास आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से शासकीय सेवा में चयन के माध्यम से सुरक्षित भविष्य और आर्थिक संबल और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदाय करना है।



निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश

संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा परिसर के लिए पुल निर्माण कार्य की उप मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लक्ष्मणबाग संस्थान की भूमि पर रीवा के लक्ष्मणबाग से कुठुलिया मार्ग में बिछिया नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व श्री शिवशेखर शुक्ला सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाकर भूमि अर्जन सहित आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को भूमि अर्जन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए, ताकि भूमि अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ एवं पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब न हो तथा सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराएं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन का महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्वविद्यालय के नवीन भवन तक सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय के महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य से संबंधित सभी प्रक्रियाएं प्राथमिकता से पूर्ण की जाएं।

प्रदेश में यूआईडीएआई के सभी 36 नए आधार सेवा केंद्र हुए क्रियाशील

आधार नामांकन एवं अपडेट की सुविधाओं की पहुंच होगी आसान, सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेंगी सेवाए

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



मध्यप्रदेश में आधार सेवाओं के विस्तार और नागरिकों को आधार संबंधी सुविधाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदेश में स्थापित किए गए सभी 36 नए आधार सेवा केंद्र क्रियाशील हो गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के बड़े भौगोलिक क्षेत्र में नागरिकों को यूआईडीएआई द्वारा सीधे संचालित आधार नामांकन एवं अपडेट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उल्लेखनीय है कि पिछले छह वर्षों के दौरान प्रदेश में यूआईडीएआई द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र केवल भोपाल और इंदौर में उपलब्ध थे। आधार सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 36 अतिरिक्त केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इन सभी केंद्रों के क्रियाशील होने से प्रदेश में यूआईडीएआई के आधार सेवा नेटवर्क का विस्तार हुआ है। नए आधार सेवा केंद्र प्रदेश के जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के साथ-साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीव्हीटीजी) की आबादी वाले जिलों में भी स्थापित किए गए हैं। इनमें अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, शिवपुरी, बालाघाट और मंडला सहित विभिन्न जिले शामिल हैं। इससे जनजातीय एवं दूरस्थ अंचलों के नागरिकों को आधार संबंधी सेवाएं प्राप्त करना आसान होगा। आधार सेवा केंद्रों में नागरिकों की सुविधा के लिए आधुनिक अवसंरचना एवं सुव्यवस्थित संचालन की व्यवस्था की गई है। सभी केंद्रों पर सप्ताह के सातों दिन आधार सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। नागरिक अपनी सुविधानुसार यूआईडीएआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इससे नागरिक अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकेंगे और केंद्रों पर प्रतीक्षा समय कम करने में मदद मिलेगी। इन केंद्रों में बैठने की समुचित व्यवस्था, आधार नामांकन एवं अपडेट के लिए आधुनिक उपकरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

भोपाल में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा आज, नड्डा होंगे शामिल

भोपाल

भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल द्वारा लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के अंतर्गत 4 नवंबर को आयोजित होने वाली विशाल पदयात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को दिनभर बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों का दौर चला। जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की टीमों, कार्यक्रम एवं सोशल मीडिया टोलियों ने बैठक कर पदयात्रा की सफलता के लिए जिम्मेदारियां संभालीं। जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति ने विभिन्न बैठकों में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आपसी समन्वय, सक्रियता और संगठनात्मक एकजुटता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तथा अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करें। तैयारियों के क्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति एवं महापौर मालती राय ने अटल पथ स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की बैठक कर पदयात्रा में सहभागिता का आग्रह किया।

एमपी अजब है–गजब है, पुल निर्माण के फाइनल बिल में 33 लाख की हेराफेरी

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

एमबी बुक की गायब, दस्तावेजो में की छेड़छाड़

सिंगरौली में म्यार नदी पुल निर्माण के फाइनल बिल में हेराफेरी किये जाने की शिकायत को ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया है। जॉच में 7.37 लाख के बिल को 40.91 लाख करने, एमबी नंबर 605 गायब करने और 16.78 लाख की पेनल्टी से बचने की साजिश के आरोप में पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन इंजीनियरों और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार सिंगरौली जिले में पुल निर्माण के नाम पर सरकारी राशि में हेराफेरी और दस्तावेजों में कूटरचना की गई है। चाचर से कुहुनिया मार्ग पर म्यार नदी में बने पुल के फाइनल बिल में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की रीवा इकाई ने शिकायत के सत्यापन के बाद एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया कि पुल निर्माण के लिए स्वीकृत अंतिम देयक 7 लाख 37 हजार 861 रुपये था, जिसे कथित तौर पर कूटरचना कर बढ़ाकर 40 लाख 91 हजार 300 रुपये कर दिया गया। इस पूरे मामले में माप पुस्तिका गायब करने, दस्तावेजों में काट-छांट और पेनल्टी से बचने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। जांच में खुलासा हुआ की म्यार नदी पुल और पहुंच मार्ग निर्माण का ठेका मेसर्स विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रीवा को दिया गया था। इसके लिए 5 फरवरी 2016 को अनुबंध निष्पादित हुआ था। अनुबंध के मुताबिक निर्माण कार्य 18 महीने में यानी 4 अप्रैल 2018 तक पूरा होना था।

भोपाल में आज से विशेष सफाई और फागिंग अभियान, तीन चरणों में होगी कार्रवाई

भोपाल। शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने और मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम मंगलवार से विशेष सफाई एवं फागिंग अभियान शुरू कर रहा है। अभियान के तहत सभी वार्डों में सुबह 6 से 11 बजे और दोपहर 12 से 3 बजे तक विशेष सफाई की जाएगी। वहीं, शाम 4 से रात 8 बजे तक पूरे वार्ड में फागिंग कराई जाएगी।



निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। संबंधित जोन के अमले को उपलब्ध वाहनों, डंपर, जेसीबी और अन्य मशीनरी के साथ एक साथ मैदान में उतरकर अधिकतम कचरा और मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। एकत्रित कचरे को निर्धारित निष्पादन स्थल तक पहुंचाया जाएगा। अभियान में स्थानीय पार्षदों को भी शामिल किया जाएगा और उनके द्वारा बताए गए स्थानों पर सफाई, अतिक्रमण हटाने सहित अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण के लिए सभी वार्डों और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित फागिंग होगी। डोर-टू-डोर कचरा वाहनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी भी कराई जाएगी। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जमा पानी की जांच की जाएगी।

राज्य स्थापना दिवस हमारी विविधता में एकता की शक्ति का उत्सवः राज्यपाल मंगुभाई पटेल



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' संकल्पना के तहत भारत के सभी राज्यों के स्थापना दिवस के आयोजन की पहल अत्यंत सराहनीय और दूरदर्शी है। यह भारत की विविधता में एकता की शक्ति का उत्सव है। एक-दूसरे के राज्यों की संस्कृति को जानने, समझने और गर्व करने का पावन प्रसंग है। हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपराओं और अनेकता में एकता के शाश्वत भाव को साकार करने का आयोजन है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की स्मृतियों को संजोने और भारत की संघीय व्यवस्था, सांस्कृतिक वैभव और अखंडता के गौरव का पर्व है। उन्होंने कहा कि राज्यों के स्थापना दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन राज्यों की लोक कला, संस्कृति की झलक को को करीब से देखने का अवसर मिलता है। सभी प्रस्तुतियां समृद्ध भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल मंगलवार को लोकभवन में 01 नवंबर को गठित मध्यप्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के स्थापना दिवस के संयुक्त समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने उक्त सभी प्रदेशवासियों को उनके राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना की। सभी प्रतिभागियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। लोकभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित समारोह में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि हमारा देश, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जहाँ विविध भाषाएँ, वेश-भूषा, परंपरा, लोक कला और जीवन मूल्यों का दर्शन होता है। मध्यप्रदेश की धरती ने सभी को सदैव अतिथि सत्कार, सद्भाव और अपनापन दिया है। यहां बसे दूसरे प्रदेशों के नागरिक हमारे परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की उपजाऊ धरती, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, उद्यमशीलता और समृद्ध मानव संसाधन देश की आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण आधार हैं। हरियाणा के नागरिक परिश्रमी, अनुशासित और प्रतिभाशाली है, जो खाद्य सुरक्षा, खेल उत्कृष्टता, विनिर्माण और सैन्य योगदान से भारत का मान बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत, ऊर्जा क्षमता, खनिज, वन और जल संपदा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चंडीगढ़ की आधुनिक नगर योजना, स्वच्छता, हरित क्षेत्र और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान देश की सुशासन संस्कृति को नई दिशा प्रदान करती हैं। योगदान यह बताता है कि भारत का विकास विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं और क्षमताओं के समन्वय से ही आगे बढ़ रहा है।

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का हत्यारा गिरफ्तार

भोपाल। राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके में रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल पिता किशनचंद अग्रवाल (70) की उनके घर में ही हत्या किए जाने की सनसनी खेज घटना में हत्या के फरार आरोपी केयर टेकर वरूण पिता राज कुमार वालमिकी (27) निवासी आशा कोलोनी, तहसील नाभा जिला पटियाला,पंजाब एवं 126-एफ लखन पुर कॉलोनी शास्त्रीपुरम आगरा (यूपी) को पुलिस आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आगरा के मथुरा रोड से दबोच लिया है। आरोपी कचरा बैग लिए हुए नजर आया तब टीम ने उसे घेराबंदी करते हुए दबोच लिया। आरोपी को लेकर टीम फौरन ही भोपाल के लिये रवाना हुई यहॉ मंगलवार सुबह करीब 5 बजे मुगलिया छाप के नजदीक आरोपी वरुण द्वारा पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। उसे शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। उसके पैर में पुलिस की गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिये हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अग्रवाल के डांटने से नाराज था। आरोपी को रिमांड पर लेकर घटना के संबध में विस्तृत पूछताछ लगातार जारी है ।

पेंशनर्स की सुविधा के लिए 4 को निशातपुरा एवं 5 नवम्बर को हबीबगंज रेलवे अस्पताल में विशेष शिविरों का आयोजन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



पश्चिम मध्य रेल के सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, निशातपुरा, भोपाल द्वारा पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 से 30 नवंबर 2026 तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री प्रफुल्ल वी. कोहाड़े के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय डोंगरा एवं सहायक कार्मिक अधिकारी श्री संदीप शर्मा के निर्देशन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य पेंशनर्स को स्वास्थ्य जांच एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में भोपाल मंडल के पांच चिकित्सा संस्थानों में निर्धारित तिथियों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 04 नवंबर 2026 को मंडल रेल चिकित्सालय, निशातपुरा; 05 नवंबर 2026 को पॉलीक्लीनिक, हबीबगंज; 12 नवंबर 2026 को डीजल शेड, इटारसी; 19 नवंबर 2026 को उप मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, बीना तथा 26 नवंबर 2026 को उप मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, गुना में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पेंशनर्स को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं एवं डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिल सके।

इसके अतिरिक्त मीटिंग हॉल, सादिकपुरा, भोपाल स्थित वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कार्यालय में भी 1 से 30 नवंबर 2026 तक कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। यहां कर्मचारी कल्याण निरीक्षकों द्वारा विशेष रूप से 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनर्स तथा पारिवारिक पेंशनर्स को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें स्वास्थ्य जांच कराने एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। शिविरों के दौरान पेंशनर्स को साइबर धोखाधड़ी से बचाव के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। उन्हें अनजान फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी संदेशों, ओटीपी साझा करने तथा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को देने से बचने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाएगी, ताकि वे डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित उपयोग कर सकें। पश्चिम मध्य रेल की इस पहल से पेंशनर्स को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया समझने, स्वास्थ्य जांच कराने तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का अवसर मिलेगा। यह प्रयास वरिष्ठ पेंशनर्स सहित सभी पेंशनर्स को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

योग सत्रों के माध्यम से रेलकर्मियों और आमजन को दिया जा रहा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ जीवनशैली का संदेश

मिशन लाइफ के तहत भोपाल मंडल में मनाया जा रहा BRICS सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**





भारतीय रेलवे द्वारा 1 से 7 नवंबर 2026 तक आयोजित किए जा रहे BRICS Sustainable Lifestyle Week के अंतर्गत भोपाल मंडल में मिशन लाइफ के तहत विभिन्न जागरूकता एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत भोपाल मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों एवं रेलवे अस्पताल में योग सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा दैनिक जीवन में सकारात्मक एवं स्वस्थ आदतों को शामिल करने का संदेश दिया गया। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सतत जीवनशैली को जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से सप्ताह के दौरान ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, खाद्य अपव्यय की रोकथाम, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी, ई-कचरे का उचित निस्तारण तथा कचरा प्रबंधन सहित सात प्रमुख विषयों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। भोपाल मंडल द्वारा इस पहल के माध्यम से रेलकर्मियों एवं आमजन को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने तथा दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली, स्वच्छ पर्यावरण एवं सतत विकास के प्रति सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।

स्वामी **एक सत प्रयास जनकल्याण समिति** के लिए मुद्रक प्रकाशक एवं **सम्पादक अमित शर्मा** द्वारा 401, जीवन छाया अपार्टमेंट, राइट टाउन, जबलपुर (मप्र) पिन: 482004 से प्रकाशित एवं पीजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482002 से मुद्रित। पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI-MPHIN/2019/78787, स्थानीय संपादक: विक्रम सिंह। E-mail:eksatbulletin@gmail.com, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9893311784